

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45]

नई विल्ली, शनिबार, नवस्थर 6, 1965 (कार्तिक 15, 1887)

No. 45]

NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 6, 1965 (KARTIKA 15, 1887)

इस भाग में सिश्न पृष्ठ संस्था दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके अर्थ Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

मोदिस

NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत 26 अक्तूब्र 1965 तक प्रकाशित किए गए थे :--The undermentloned Gazettes of India Extraordinary were published up to the 26th October 1965 :--

क्षंक (Issue No.)	संख्या और तारीख (No. and Date)	द्वारा जारी किया गया (Issued by)	बिषय (Subject)
144.	No. F. 4(28)-W & M/65, dated 19th October, 1965. No. F. 4(29)-W & M/65, dated 19th October, 1965.	Ministry of Finance. Do.	Issue of 41 percent. National Defence Loan, 1968 and 41 percent. National Defence Loan, 1972. National Defence Gold Bonds, 1980.
145.	No. 87-ITC(PN)/65, dated 19th October, 1965.	Ministry of Commerce.	Registration of Agency. Agreements for the purpose of issue of letters of authority.
	No. 88-ITC(PN)/65, dated 19th October, 1965.	Do.	Import of Capital Goods and other items under National Defence Remittance Scheme.
146.	No. PN (U. K. Licensing)/7 of 1965, dated 26th October, 1965	Do.	Scheme for the licensing of cotton textiles for export to the U. K. from India—Balance quota for 1965.
147.	No. 89-ITC(PN)/65, dated 26th Octobor, 1965.	Do.	U. S. AlD Programme—chartering of Ocean Vessels and embargo on certain Vessels for transport of AID financed goods.

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्नों की प्रतियां प्रकाशन प्रवन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांगपत्र भेजने पर भेज दी आएंगी। मांग-यद्य प्रवन्धक के पास इन राजपत्नों के जारी होने की तारीख़ से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिए।

Copies of the Gazettes Extraordinary mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची (CONTENTS)

	पृष्ठ		पृष्ठ
	(Pages)		(Pages)
भाग !—संड !—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों,		भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	,
विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं भाग I—खंड 2—(रक्षा मंद्रालय को छोड़कर) भारत	595	भाग I - खंड 4 रक्षा मंत्रालय द्वारा आरी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोश्रतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं	565
सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय हारा जारी की गई सरकारी अफसरों की		भाग II— खंड 1अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	_
नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं	929	भाग II— बंड 2विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की स्पिटें	_

Administrations of Union Territories) _

1657

1965

. .

..

1555

भाग I-- खण्ड 1

PART I-SECTION 1

(रका मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा अञ्चलम न्यान्यक्रय द्वारा कारी की गई विश्वीतर निषमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिमुखनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

राष्ट्रपति सचिवासम

नई दिल्ली, दिनांक 14 अगस्त 1965

सं० 88-प्रेज/65—-राष्ट्रपित गुजरात पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये राष्ट्रपित का पुलिस तथा अग्निशमन सेवा पदक प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम तथा पव श्री भाऊसाहेब शिवाजीराव शिक्, सहायक कमाण्डेंट (स्थानापन्न), राज्य आरक्षित पुलिस दल, गुजरात ।

सेवाओं का बिवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया

अप्रैल, 1965 में कछ के रन में भारत-पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान के भारी आक्रमण के समय श्री भाऊसाहेब शिवाजीराव शिकें छाद बेट में राज्य आरक्षित पुलिस की एक गैरिसन की कमांड कर रहे थे। जब सरदार पुलिस चौकी पर हमला हुआ, तब गलु की छाद बेट के सामने एक भारी सेना एकत्रित थी। इस डराने की कोशिशों और संख्या में बहुत अधिक और भारी हथियारों से लैस शत्र की परवाह न करते हुए श्री शिर्कों ने उस समय तक सीमा पर कामयाबी के साथ गस्त लगाना जारी रखा जब तक कि 21 अप्रैल 1965 को शतु ने हनुमान तलई पर स्थित चौकी पर गोलाबारी नहीं की। 23 अप्रैल को विधी की पुलिस चौकी पर भारी गोलाबारी की गई और 24 अप्रैल को शलु के तोपखाने ने छाद बेट की चौकी पर मझोली मशीनगनों और 3" मार्टरों से गोले बरसाना शुरू कर दिया । पाकिस्तानी सेना छाद बेट चौकी की घेराबन्दी से 1200 गज दूर तक आगे आ गई किन्तु श्री शिर्के के लिये योग्य नेतृत्व में पुलिस दल ने शत्रु की सेना को बलपूर्वक उलझाये रखा और 3 घंटे चलने वाली एक भयंकर लड़ाई के बाद उनके केन्द्रित हमले को पछाड़

इस मुठभेड़ में श्री भाऊसाहेब णिवाजीराव शिर्के ने उत्कृष्ट वीरता, उदाहरणीय साहस, नेतृत्व तथा उच्च स्तर की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्निशमन सेवा पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है।

सं० 89-प्रेज् / 65---राष्ट्रपति गुजरात पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्निशमन सेवा पदक प्रदान करते हैं:---

अधिकारी का नाम तथा पर

श्री भास्कर आनन्दराव देवकर, हैड कान्स्टेबल, राज्य सुरक्षित पुलिस दल—-प्रुप-II गुजरात।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रवान किया गया

21 अप्रैल 1965 को सशस्त्र पाकिस्तानी सेना ने छाद बेट की हनुमान तलई पर स्थित चौकी की गैरिसन पर भारी गोलाबारी की। शत्रु की भारी गोलाबारी के फलस्वरूप उस चौकी का एक हैंड कान्स्टेबल लापता पाया गया। चौकी के कमांडर ने हैंड कान्स्टेबल भास्तर आनन्दराव देवकर को लापता हैड कान्स्टेबल की खोज के लिये तैनात किया। शत्रु की गोलाबारी के बावजूद हैड काम्स्टेबल देवकर रवाना हुआ और हैंड कान्स्टेबल का शव पाने और उसे उपकरण नथा गोलाबारूद सहित छाद बेट चौकी पर लाने में सफल हो गया। 23 और 24 अप्रैल को जब शत्रु ने उक्त चौकी पर मझोली मशीनगनों और 3" मार्टरों से गोलाबारी करना शृरू किया तब हैड कान्स्टेबल देवकर चौकी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहा और उसने अपने जीवन पर संकट ले कर अत्यावश्यक हथियार और गोलाबारूद को एक अधिक सुरक्षित स्थान पर हटाने की व्यवस्था की।

हैड कान्स्टेबल भास्कर आनन्द राव देवकर ने अपने व्यक्तिगत मुरक्षा की तिनक भी परवा किये बिना उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा उच्च स्तर की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्निणमन सेवा पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत बीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 24 अप्रैल 1965 से दिया जायेगा।

सं० 90-प्रेज /65---राष्ट्रपति पुलिस गुजरात के निम्नांकित अधिकारी की उसकी बीरता के लिये पुलिस पदक प्रदान करते हैं:---

अधिकारी का माम तथा पव

श्री बलराम रामचन्द्र मालसुरे, कान्स्टेबल, राज्य आरक्षित पुलिस दल, ग्रुप-II, गुजरात ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया

जब 23 और 24 अप्रैल 1965 को सशस्त्र पाकिस्तानी सेना ने छाद बेट की पुलिस चौकी पर हमला किया तब कांस्टेबल बलराम रामचन्द्र मालसुरे राज्य आरक्षित पूलिस दल के उस चौकी पर नियुक्त दस्ते में थे। 24 अप्रैल को छोटे पुलिस दक्ष के लिये जब संख्या में अधिक शत्रु सेना की भारी और बराबर तोपों तथा मार्टरों द्वारा गोलाबारी के ठोस एवं केन्द्रित हमले का सामना करना असम्भव हो गया, तब चौकी कमांडर ने उस चौकी के रिकार्ड, अतिरिक्त हथियार तथा गोलाबारूद को हटा कर सुरक्षित स्थिति में से जाने का आदेश दिया । ऐसी भारी गोलाबारी में इस अत्यन्त दुष्कर एवं खतरनाक कार्य में कान्स्टेबल बलराम मालसूरे अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुये । गोलाबारी की उपेक्षा करते हुए और अपनी स्वयं की सुरक्षा की तनिक परवाह किये बिना, कान्स्टेबल मालसुरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम-घूम कर बहुमृल्य रिकार्ड, अतिरिक्त हथियार तथा उपकरणों को एकत्नित कर सुरक्षित स्थान में ले जाने के लिये गाड़ियों में लादा। इस सारे समय कान्स्टेबल बलराम रामचन्द्र मालसुरे ने असाधारण माहस और उच्च स्तर की कर्सव्य-परायणता का परिचय दिया ।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत नीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फसस्वरूप नियम 5

के अन्तर्गत विशोष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 24 अप्रैल 1965 से दिया जायगा।

सं० 91-प्रेज/65—राष्ट्रपति गुजरात पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम तथा पव श्री मंगर्लासह ईश्वरसिंह उरवाल, हैंड कान्स्टेबल (स्थानापन्न), राज्य आरक्षित पुलिस दल, गुजरात ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया

अप्रैल, 1965 में जब सशस्त्र पाकिस्तानी सेना ने छाद बेट की पुलिस चौकी पर हमला किया तब हैड कान्स्टेबल मंगलसिंह र्दश्वर सिंह अरवाल राज्य आरक्षित पुलिस दल की उस चौकी पर तैनात दस्ते में था । सरदार चौकी पर आक्रमण करने से पूर्व जब शतु ने कंजरकोट पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन किया, हैड कान्स्टेबल डरवाल ने पर्याप्त व्यक्तिगत संकट को उठाते हुए टोह गरत लेने तथा सीमा के नज़दीक अपनी गाड़ी को ले जाने का नेतृत्व करने में महान भनोयोग का परिचय दिया । पाकिस्तान रेंजरों की धमकियों के बावजूद वह अपनी गाड़ी को ठीक सीमा तक ले जा कर गरत लगाते रहें। 22 अप्रैल को हनुमान तलई क्षेत्र में गोलाबारी के बीच से हैड कान्स्टेबल डरवाल एक हैड कान्स्टेबल का भव उठा लाये। पुनः 23 और 24 अप्रैल 1965 को जब छाद बेट पर जोरों से गोलाबारी हो रही थी, हैंड कांस्टेबल डरवाल आवश्यक कागज-पत्न, हथियार और उपकरणों को सुरक्षित स्थानों पर ले गए और शतू की भारी गोलाबारी के बीच से चौकी के जवानों के लिये खाना लाये।

हैड कान्स्टेबल मंगलसिंह ईश्वर सिंह इरवाल ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की तिनक भी परवाह न कर उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा उच्च रतर की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 24 अप्रैल 1965 से दिया जायगा।

वाई० डी० गण्डेविया, राष्ट्रपति के सचिव

षोजना आषीग

संच रन

जन सहयोग सम्बन्धी राष्ट्रीय सलाहकार समिति

नई दिल्ली, दिनांक 26 अक्तूबर 1965

सं० 6(1)/65-पब०--1958 में भारत सरकार ने जन सहयोग सम्बन्धी राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया था। इसका काम (1) राष्ट्रीय विकास के सम्बन्ध में जन सहयोग की प्रगति की समीक्षा तथा विश्लेषण करना, (2) योजना की पूर्ति के सम्बन्ध में, समय-समय पर जन सहयोग की प्रगति के लिए योजना आयोग को सलाह देना, और (3) जन सहयोग से सम्बन्धित नीति और कार्यक्रमों के बारे में सुझाव देना तथा सिफारिश करना था।

- 2. इस समिति को अधिक प्रतिनिधिक और व्यापक बनाने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने इसका निम्न प्रकार से पुनर्गठन करने का निश्चय किया है:—
 - (क) योजना आयोग के सदस्य,
 - (ख) श्री अमरनाथ विद्यालंकार, संसद् सदस्य।
 श्री एम० एस० गुरुपदा स्वामी, संसद् सदस्य।
 श्री जयपाल सिंह, संसद् सदस्य।

श्री सी० आर० बासप्पा, संसद् सदस्य ।
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती, संसद् सदस्य ।
श्री नाथ पाई, संसद् सदस्य ।
श्री वी० एन० प्रसाद, संसद् सदस्य ।
श्री मतीदुर्गाबाई देणमुख ।
प्रोफेसर एन० अर० मलकानी ।
जनरल के० एम० करियाप्पा ।
श्री टी० एस० भारडे
श्री बी० वी० बालिगा ।
श्री ईश्वरभाई जे० पटेल ।

`श्री ईश्वरभाई जे० पटेल । (ग) निम्न संगठनों में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि :---शिक्षा का अखिल भारतीय संघ। अखिल भारतीय महिला परिषद् । अखिल भारतीय पंचायत परिषद्। अखिल भारतीय केन्द्रीय महिला अन्न परिषद् । अखिल भारतीय भूतपूर्व सैनिक संघ । अखिर भारतीय नशाबन्दी परिषद् । अखिल भारतीय बालक स्काउट्स संघ । अखिल भारतीय नैतिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य संघ। अखिल भारतीय सामाजिक कार्य संस्थाओं का संघ । ग्राम सेवा संगम । भारत सेवक समाज । भारत कृषक समाज। भारतीय आदिम जाति सेवक संघ । भारत साधु समाज। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स । भारतीय ग्रामीण महिला संघ । बालकन-जी-बाड़ी। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड । भारत कैथोलिक चैरिटीज । सामाजिक विकास परिषद् । दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा। भारतीय परिवार नियोजन संघ । गांधी स्मारक निधि। हरिजन सेवक संघ । भारतीय रेडकोस समिति । सामाजिक कार्य का भारतीय सम्मेलन । भारतीय बाल कल्याण परिषद् । भारतीय सहकारी संघ। कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक निधि । अध्यापक शिक्षक राष्ट्रीय संघ । राष्ट्रीय कैंडेट कोर और सहायक कैंडेट कोर । वाई० एम० सी० ए० की राष्ट्रीय परिषद्। भारतीय राष्ट्रीय अभिभावक अध्यापक संघ । भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ । राष्ट्रीय महिला परिषद् । राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् । विश्व मामलों की भारतीय परिषद् । राष्ट्रीय उपभोक्ता सेवा । राम कुष्ण मिशन । राष्ट्रभाषा प्रचार समिति । जन सेवक समिति । संयुक्त सदाचार समिति । भारतीय क्षयरोग समिति । भारतीय चिकित्सक संघ । ऐच्छिक रुधिराधान सेवा ।

भारतीय युवा महिला क्रिश्चियन संघ ।

- 3. योजना आयोग के अध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष होंगे। श्री क्रुष्ण प्रसाद अवैतिनिक सचिव का काम करते रहेंगे।
- 4. सिमिति समय-समय पर ऐसे विशिष्ट कार्यों के लिए सदस्यों को, सहयोजित कर सकेगी जिनके लिए उनका संयोजन वह आवश्यक समझे ।

आपृंश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत सरकार के राजपत्न में प्रकाशित किया जाए ।

कें ० ए० पी० स्टीवेन्सन, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

मियम

नई दिल्ली-11, दिनांक 6 नवम्बर 1965

सं० 8/30/65- C.S. II — संघ लोक आयोग द्वारा निम्न-लिखित सेवाओं पदों में अस्थायी रिक्तियों में नियुक्ति के लिए ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के नियम सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं:—

- (i) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा-ग्रष्ड II
- (ii) रेलवे बोर्ड सचिवालय आश्लिपिक सेवा ग्रेड II
- (iii) भारतीय विदेश सेवा (ख)-(आशुलिपिकों का सब कैडर II), और
- (iv) भारत सरकार के कुछ ऐसे कार्यालयों के आणुलिपिकों के पद जो केन्द्रीय सचिवालय आणुलिपिक सेवा भारतीय विदेश सेवा रेलवे बोर्ड सचिवालय आणुलिपिक सेवा में णामिल नहीं है और चुनाव आयोग के कार्यालय में ऐसे पद ।
- इस परीक्षा का संचालन संघ लोक मेवा आयोग द्वारा, नियमों के परिशिष्ट I में निर्धारित विधि से किया जायगा।

परीक्षा की तारीखें और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

- 3. (1) उम्मीदवार को अवश्य ही या तो
- (क) भारत का नागरिक होना चाहिए, या
- (ख) सिक्किम की प्रजा, या
- (ग) नैपाल की प्रजा, या
- (ष) भूटान की प्रजा, या
- (ड) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से पहली जनवरी 1962 से पूर्व भारत आ गया हो, या
- (च) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से पाकिस्तान से प्रव्रजन किया हो ।

परन्तु ऊपर की (ग), (घ), (घ) (च) कोटियों के अन्तगंत आने वाले उम्मीदवारों के पास भारत सरकार द्वारा दिया गया पात्रता का प्रमाण पत्न होना चाहिए यदि वह (च) कोटि में आता हो तो पात्रता का प्रमाण पत्न उसकी नियुक्ति की तारीख से लेकर केवल एक साल के लिए मान्य होगा । उसके बाद उम्मीदवार की नोकरी तभी जारी रखी जायगी जब वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

लेकिन नीचे लिए गए उम्मीदवारों के मामलों में पान्नता प्रमाण पक्ष से लेना आवश्यक नहीं होगा:----

> (i) वे व्यक्ति जिन्होंने 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत में प्रयुजन किया था और जो तब से आमतौर पर भारत में ही रह रहे हैं।

- (ii) वे व्यक्ति जिन्होंने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन किया था और संविधान के अनुच्छेद के अधीन स्वयं को भारत नाग-रिक के रूप में पंजीकृत करा लिया है।
- (iii) ऊपर की (च) कोटि के वे गैर-नागरिक, जो संविधान लागू होने की तारीख अर्थात् 26 जनवरी 1950 से पहले भारत सरकार की सेवा में आए और तब से लगातार नौकरी कर रहे हैं और जिनके सेवा काल में कोई म्रांग (क्रेक) नहीं हुआ है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के सेवाकाल में भंग हुआ हो तो और उसने 26 जनवरी 1950 के बाद उक्त सेवा दुबारा शुरू की हो तो उसे भी औरों की तरह पान्नता प्रमाण पन्न देना होगा ।

हसके अलावा एक गर्त यह भी है कि उपर्युक्त (ग) (घ) और (उ) कोटियों के उम्मीदवार भारतीय विदेश सेवा (ख) (आशुलिपिको के सब कैंडर का ग्रेड II) में नियुक्ति के पात नहीं माने जाएंगे।

- (2) परीक्षा में वह उम्मीदवार भी प्रवेश पा सकेगा जिसके लिए पालता प्रमाण पत्न आवश्यक हो और उसे सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाणपत्न दिए जाने की शर्त के साथ अस्थायी रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है।
- 4. जो उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का न हो, या संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी का निवास न हो, या अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह का निवासी न हो, या लंका से प्रत्यावर्तित न हो, या संघ राज्य क्षेत्र गोआ दमन और दियू का निवासी न हो, या केन्या, उगांडा और संयुक्त गणतंत्र तंजानिया (भूतपूर्व टांगानीका और जंजीबार) से प्रव्रजन कर के न आया हो, प्रतियोगिता में दो से अधिक बार नहीं बैठ सकेगा, किन्तु यह प्रतिबंध उस परीक्षा से लागू होगा जो सन् 1962 में हुई थी।
 - नोट:—यदि उम्मीदवार एक या अधिक सेवाओं/पदों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में बैठा हो तो इस नियम के प्रयोजन के लिए यह मान लिया जायगा कि वह प्रतियोगिता-परीक्षा में एक साथ सब सेवाओं/पदों के लिए बैठ चुका है।

नोट:--यदि उम्मीदवार न एक या अधिक विषयों की परीक्षा धी हो तो यह माना जायगा कि वह प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ चुका है ।

- 5. (क) इस परीक्षा के उम्मीदवार के लिए यह जरूरी है कि उसकी आयु पूरे 18 साल की हो गई हो और 1 जनवरी 1966 को उसकी आयु पूरे 24 साल की न हुई हो, अर्थात् उसका जन्म 2 जनवरी 1942 से पहले और 1 जनवरी, 1948 के बाद न हुआ हो।
- (ख) उक्त ऊपरी आयु सीमा में उन व्यक्तियों के मामले में 35 वर्ष की आयु तक की छूट दी जायगी जो भारत सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में आशु लिपिकों (इसमें अंग्रेजी के इलावा अन्य भाषाओं के आशु लिपिक भी शामिल हैं) लिपिकों के पदों पर नियुक्त हैं और 1 जनवरी 1966 के उक्त सरकार के अधीन उपरोक्त पदों पर कम से कम तीन साल से लगातार काम कर रहे हों। किन्तु उपरोक्त आयु सम्बन्धी छूट उन व्यक्तियों को नहीं दी जायगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पहले ली गई परीक्षाओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसीं में आगु लिपिक के रूप में नियुक्त किए जा चुके हैं।
 - (i) केन्द्रीय सचिवालय आगुलिपिक सेवा, या
 - (ii) रेलवे बोर्ड सिचवालय आशुलिपिक सेवा या

- (iii) भारतीय विदेश सेवा (ख) या
- (iv) गुप्त वार्ता विभाग ।
- नोट:--डाक व तार विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में नियुक्त आर० एम० एस० सार्टरों की सेवा उपरोक्त नियम 5 (ख) के लिए लिपिक वर्ग में की गई सेवा मानी जायगी।
- (ग) उपरोक्त सभी मामलों में ऊपरी आयु सीमा के बारे में निम्म अवधि तक और भी छूट दी जा सकेगी:—
 - (i) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जातियों अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्धित हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक,
 - (ii) यदि उम्मीदवार सचमुच पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित हो और 1 जनवरी 1964 या उसके बाद प्रवजन करके भारत में आ चुका हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,
 - (iii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से सम्बन्धित हो और सचमुच ही पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित हो कर 1 जनवरी 1964 या उसक बाद प्रव्रजन कर भारत आ चुका हो तो अधिक से अधिक 4 वर्ष तक,
 - (iv) यदि उम्मीदवार संघ राज्य क्षेत्र पांडीचेरी का निवासी हो और किसी न किसी स्तर पर उसकी शिक्षा फैंच भाषा के माध्यम से हुई हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक,
 - (v) यदि उम्मीदवार अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह का निवासी होतो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक
 - (vi) यदि उम्मीदवार भारत का नागरिक हो और लंका से प्रतयावर्तित हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक और
 - (vii) यदि उम्मीदिवार संघ राज्य क्षेत्र गीआ, दमन और दियु का निवासी हो तो अधिक-से-अधिक तीन वष तक.
- (viii) यदि उम्मीदिवार भारतीय मृल से सम्बद्ध है और केन्या, उगांडा और संयुक्त तंजानिया गणतंत्र (भूतपूर्व तांगानीका और जजीबार) से प्रत्यावर्तित हो।

ऊपर बताई गई स्थितियों के अलावा ऊपर निर्धारित आयु सीमाओं में किसी भी हालत में छुट नहीं वी जा सकेगी।

ध्यान दें:—(i) यदि किसी उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने के लिए ऊपर अनुच्छेद 5 (ख) में कही गई आयु सम्बन्धी रियायतें मिली हों और वह आवेदन पत्न देने के बाद परीक्षा में बैठने से पहले या बाद में, नौकरी से त्याग पत्न दे दे या पदच्युत कर दिया जाय तो उसे नियुक्ति का पात नहीं माना जायगा जेकिन यदि आवेदन-पत्न प्रस्तुत करने के बाद नौकरी या पद से उसकी छंटनी हो जाय तो वह पात बना रहेगा।

- (ii) यदि कोई स्टेनोप्राफर/क्लक, सक्षम अधिकारी के अनु-मोदन से संवर्ग से बाहर किसी पद (एक्स केंडर पोस्ट) पर प्रति-नियुक्त हो तो अन्य सब प्रकार से परीक्षा में प्रवेण पाने का पान होने पर उमे भी इसका पान माना जायगा ।
- 6. जो उम्मीदवार गुप्तवार्ता विभाग में या उसके अर्धान नियुक्त है उन्हें, अन्यथा उपयुक्त होने पर, केवल गुप्तवार्ता विभाग के पदों के लिए ही परीक्षा में प्रवेश मिल सकेगा। अन्य उम्मीद-वारों को, अन्यथा प्रवेश पाने का पात होने पर उस सभी सेवाओं कार्यालयों के लिए परीक्षा में प्रवेश मिलेगा। जिनके लिए इस परीक्षा के परिणामों द्वारा भरती की जाती है।

- 7. उम्मीदवारों के नीचे लिखी परीक्षाओं में से कोई एक आवश्यक पास की हो और उनके पास उनमें से किसी एक का प्रमाण पक्ष अवश्य होना चाहिए:——
 - (क) भारत के केन्द्रीय संविधान मण्डल अथवा किसी राज्य विधान-मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा निगमित किसी विध्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा अथवा ऐसे विश्वविद्यालय द्वारा उसके समक्ष मान्यता-प्राप्त कोई परीक्षा;
 - (ख) किसी राज्य के णिक्षा बोर्ड द्वारा माध्यमिक स्कूल कोर्स के अंत में शालान्त (स्कूल लीर्विग), माध्यमिक स्कूल; हाई स्कूल या ऐसे किसी और प्रमाण पत्न के के लिए ली गई कोई परीक्षा जिसे वह राज्य सरकार नौकरी में प्रवेश के लिए मैट्टिक के समक्ष मानती हो।
 - (ग) कैम्ब्रिज स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा (सीनियर) कैम्ब्रिज);
 - (ध) राज्य सरकारों द्वारा ली गई यूरोपीय हाई स्कूल परीक्षा;
 - (क) दिल्ली पोलीटेक्नीक के तकनीकी हायर सेकेंडरी स्कूल की दसवीं कक्षा का प्रमाण पक्ष;
 - (घ) किसी मान्यता-प्राप्त हायर सेकेंखरी स्कूल या इंडियन स्कूल सार्टीफिकेट परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार कराने वाले मान्यता-प्राप्त स्कूल की दसवीं कक्षा का प्रमाण-पन्न;
 - (छ) जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली की जूनियर परीक्षा, केवल जामिया में वस्तुतः (बोनाफाइड) रहने वाले छाक्षों के लिए;
 - (ज) बंगाल (साइंस) स्कूल सर्टिफिकेट;
 - (झ) नेशनल काउन्सिल आफ एजूकेशन (राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्) आदवपुर, पश्चिमी बंगाल की शुरू से लेकर अब तक की फ़ाइनल स्कूल स्टेंडर्ड परीक्षा;
 - (ञा) पांडिचेरी की नीचे फेंच परीक्षाएँ, (I) क्रीबे एिलमेतेयर (II) क्रीबे द 'एंसीमा' प्रीमियेर द लाग इंदियेन (III) क्रीबे देएत्युद यू प्रीमियेर सिकली (IV) क्रीबे द एंसीमा प्रीमियेर सुपीरियेर दे लाग इंदियेन और (V) क्रीबे दे लाग इंदियेन (वनिकूलर);
 - (ट) इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट आफ एजूकेशन;
 - (ठ) भारतीय नौसेना का हायर एज्केशनल टेस्ट;
 - (ड) एडवांस्ड क्लास (भारतीय नौसेना) परीक्षा;
 - (ढ) सीलोन सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा;
 - (ण) ईस्ट बंगाल सेकॅडरी एजुकेशन बोर्ड, ढाका द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्न;
 - (त) नेपाल सरकार की स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट परीक्षा;
 - (य) एंग्लोवनिक्लर स्कूल लीविंग समर्टिफिकेट (बर्मा)
 - (द) बर्मा हाई स्कूल फाइनल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट;
 - (ध) शिक्षा विभाग, बर्मा (युद्ध-पूर्व) की एंग्लोवनिकुलर हाई स्कूल परीक्षा;
 - (न) बर्मा का पोस्ट-वार स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट;
 - (प) गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद की 'विनीत' परीक्षा
 - (फ) गोआ, दमन और दियु में एक पुर्तगाली परीक्षा लाइ-मियुमं के पांचवें वर्ष में पास;
 - (ब) कोई अन्य परीक्षा, जिसे संघ लोक सेवा आयोग उक्त परीक्षाओं के समक्ष मान्यता दे दे।

- नोह-1. अपबाद के मामलों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे उम्मीद-वार को भी परीक्षा में बैठने का अधिकारी मान सकता है जिसने उपर्युक्त परीक्षाओं में से कोई भी पास नहीं की, बशर्तों के उसने अन्य संस्थाओं द्वारा की जाने वाली ऐसी परीक्षाएं पास की हैं जिनका स्तर आयोग के विचार में उसे परीक्षा में बैठने का अधिकारी बना देता है ।
- नोट--- 2. यदि कोई उम्मीदवार किसी ऐसी परीक्षा में बठ चुका हो, जिसमें उत्तीर्ण होने पर वह इस परीक्षा में बैठ सकता है लेकिन जिसके परिणाम की सूचना उसे अभी तक नहीं मिली हो तो ऐसी स्थिति में वह इस परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन-पक्त भेज सकता है। जो उम्मीदवार उक्त किसी अहंक (क्वालिफ़ाइंग) परीक्षा में बैठना चाहते हों, वे भी आवेदन-पन्न दे सकते हें बगर्ते कि वह अहंक परीक्षा इस परीक्षा के गुरू होने से पहले समाप्त हो जाय । ऐसे उम्मीदवार यदि अन्य शर्ते पूरी करते हों तो उन्हें परीक्षा में बैठने दिया जायगा, किन्तु परीक्षा में बैटने की अनुमति अन्तिम होगी और यदि वे उक्त परीक्षा पास करने का प्रमाण जल्दी से जल्दी और हर हालत में इस परीक्षा के गुरू होने की तारीख से अधिकाधिक दो महीने के अन्दर-अन्दर प्रस्तुत न करते तो यह अनुमति रद्द कर दी जा सकती है।
- 8. (क) जिस पुरुष उम्मीदवार की एक से अधिक जी वित पित्नां हो या जो एक पत्नी से जीवित रहने पर भी किसी ऐसी स्थिति में विवाह करें कि वह विवाह उक्त पत्नी के जीवित रहने की अवधि में किए जाने के कारण शून्य (वायड) हो जाए तो उसे उन सेवाओं पदों पर नियुक्ति का, जिनके लिए इस प्रतियोगिता-परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्तियों की जाती हैं, तब तक पात नहीं माना जाएगा तब तक कि भारत सरकार संतुष्ट न हो जाए कि ऐसा करने से विशेष कारण हैं और पुरुष उम्मीदवार की इस नियम से छूट न दे दे ।
- (ख) जिस महिला उम्मीदवार का विवाह इस कारण शून्य (वायड) हो कि उकत विवाह के समय उसके पति की एक जीवित पत्नी पहले से हैं या जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी उक्त विवाह के समय एक जीवित पत्नी हो, वह उन सेवाओं पदों में से किसी पर नियुक्ति की, जिनके लिए इस प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्तियां की जाती है, तब तक पान नहीं मानी जाएगी जबतक कि भारत सरकार संतुष्ट न हो जा कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, और उस महिला उम्मीदवार को इस नियम से खूट न दे दे।
- (ग) कोई भी व्यक्ति जिसने किसी विदेशी राष्ट्रिक से विवाह किया हो भारतीय विदेश सेवा (ख) में नियुक्ति नहीं पा सकेगा ।
- 9. जो उम्मीदवार स्थायी या अस्थायी हैसियत में पहले से ही सरकारी सेवा कर रहा हो, उसे इस परीक्षा में बठने से पहले अपने विभाग-अध्यक्ष की अनुमति अवश्य ले लेनी चाहिए।
- 10. उम्मीयवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोप नहीं होना चाहिए जिसे वह संबंधित सेवा पद के कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक न निभा सके। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह शात हो कि वह इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियक्ति नहीं की जाएगी। केवल उन्हीं उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा की जाएगी। केवल उन्हीं उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा की जाएगी जिनकी नियक्ति पर विचार किए जाने की संभावना हो।
- 11. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपान्नता के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

- 12. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने बिया जायगा जब तक उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण पन्न (सार्टिफिकेट आफ् एडमिशन) न हो।
- 13. उम्मीदवारों को आयोग की विज्ञाप्ति की संलिग्निका में निर्धारित फीस देनी होगी। उक्त संलिग्निका में बताई गई मान्ना को छोड़ कर न तो फीस की वापसी की किसी प्रार्थना पर विश्वार किया आएगा और न ही उक्त फीस किसी दूसरी परीक्षा या चुनाव के लिए आरक्षित (रिजर्व) की जा सकती है।
- 14. यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोई कोशिश करेगा तो उसे परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य करार दिया जाएगा।
- 15. यदि यह पता लगे कि उम्मीदवार ने किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी परीक्षा दिलवाई है या जारी प्रमाण पत्न आदि पेश किए हैं जिनमें कोई हेराफेरी की गई है या कोई ऐसी बात लिखी है जो गलत है या झूठी है या कोई तथ्य छिपाया है या परीक्षा भवन में अनिचत तरीकों से काम लिया है या कान लेने की कोशिश की है या परीक्षा में बैठने के लिए किसी और अनियमित या अनुपयुक्त तरीके से काम लिया है या परीक्षा भवन में अनुचित आचरण किया है तो उस पर आपराधिक अभियोग (किमिनल प्रोसीक्यूशन) चलाया जा सकता है और साथ ही उसे हमेशा के लिए या किसी विशेष प्रविध के लिये:—
 - (क) स्थायी अथवा अस्थायी रूप से (i) आयोग, उम्मीद-वारों के चुनाव के लिए ली जाने वाली किसी परीक्षा मा इत्टरव्यू में शामिल होने से रोक सकता है, और (ii) केन्द्रीय सरकार, सरकारी नौकरी करने से रोक सकती हैं।
 - (ख) यदि वह पहले से ही सरकारी सेवा में नियुक्त हो तो उसके खिलाफ उपयुक्त नियमों के अंतर्गत अनुशास-नात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- 16. जिस प्रकार भारत सरकार निर्धारित करेगी उस प्रकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे।

अनुस्चित जातियों/अनुस्चित आदिम जातियों के अर्थ हैं अनुस्चित जातियों/अनुस्चित आदिम जातियों की सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956 जैसा कि वह अनुस्चित जातियां/अनुस्चित जातियां/अनुस्चित जादिम जातियां (संशोधन) अधिनयम, 1956 संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुस्चित जाति-आदेश, 1959 संविधान (अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुस्चित जातियां आदेश संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुस्चित जातियां आदेश, 1962 और संविधान (पांडिचेरी) अनुस्चित जातियां आदेश, 1964 के साथ मिला कर पढ़ा जाय, में उल्लिखित कोई भी जातियां।

17. परीक्षा के बाद आयोग, उम्मीदवारों की, अंतिम रूप से प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवरता सूची बनाएगा और परीक्षा द्वारा भरे जाने वाले पदों की संख्या (असुरक्षित) तक उस कम से नियुक्ति के लिए उनके नामों की सिफ़ारिश करेगा।

लेकिन यह भी शर्त है कि जब आयोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के किसी ऐसे उम्मीदवार को, जो किसी सेवा/पद के लिए आयोग द्वारा निर्धारित मान के अनुसार योग्य सिद्ध न हो, पर फिर भी आयोग उसे उस सेवा पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित कर दे और इससे प्रशासनिक कुशलता में किसी प्रकार का व्याघात होने का भय न हो तो वह उस सेवा/पद में यथास्थित अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित खाली पदों पर नियुक्ति का हकवार होगा ।

नोट---1. आवेवन-पत्र भरते समय उम्मीदवार द्वारा बताई गई पसंदों पर उचित ध्यान दिया जाएगा (आवेदन- पत्न के खाना 28 को देखिए) लेकिन उम्मीदवार को ऐसी किसी भी सेवा में ऐसे किसी भी पद पर नियुक्त किया जा सकता है जिसके लिए परीक्षा ली गई हो।

ध्यान वें—2. उम्मीदवारों के योग्यताक्रम के अनुसार उनके नामों की एक आरक्षित सूची (रिजर्व लिस्ट) भी बनाई जा सकती है, जिसमें से बाद में, किन्तु स्टेनोग्राफरों की अगली परीक्षा के परिणामों की घोषणा होने से पहले, उम्मीदवारों की नियुक्ति सैन्द्रल सेकेटरिएट स्टेनोग्राफर सर्विस ग्रेड II में की जा सकती है। जिन उम्मीदवारों की एक पसंद सेन्द्रल सेकेटरिएट स्टेनोग्राफर सर्विस भी हो, उन्हें अपने आवेदन-पत्नों में यह साफ-साफ लिखना चाहिए कि क्या ऐसी आरक्षित सूची तैयार करते समय उन्हें भी शामिल किए जाने पर विचार किया जाए ?

नोट---2. हरेक उम्मीदवार को परीक्षा-फल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग अपने विवेकानुसार करेगा और आयोग परिणामों के बारे में उनसे कोई पत्न व्यवहार नहीं करेगा ।

18. परीक्षा में पास हो जाने से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार इस सेवा पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से योग्य हैं।

19. उन सेवाओं पदों के बारे में सेवा की शर्तें संक्षिप्त रूप से परिशिष्ट II में दी गई है जिनके लिए इस परीक्षा द्वारा भर्ती की जा रही है।

के० त्यागराजन, अवर सचिव

परिशिष्ट—I

 परीक्षा के विषय, परीक्षा के लिये दिया गया समय और प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक इस प्रकार होंगे:

. विषय	दिया गया समय	अधिकतम अंक
(1) अंग्रेजी . (2) सामान्य ज्ञान . (जनरल नालेज)	 3 ਬੰਟੇ 3 ਬੰਟੇ	100

भाग ख : लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों के लिये शार्ट-हैंड परीक्षा । 300

नोट:---

- (i) उम्मीदवारों की परीक्षा के लिये दो डिक्टेशन दिए जाएंगे। पहला 120 शब्द प्रति मिनट की गति पर, जो सात मिनट का होगा; और दूसरा 100 शब्द प्रति मिनट की गति पर, जो दस मिनट का होगा। इन्हें उम्मीदवारों को ऋमशः 45 और 50 मिनट में टाइप कर लेना होगा।
- (ii) जो उम्मीदवार 120 शब्द प्रति मिनट वाले डिक्टेशन की न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे उन्हें उन उम्मीद-वारों से ऊपर माना जाएगा, जो 100 शब्द प्रति मिनट वाले डिक्टेशन में वही स्तर प्राप्त करें। इसके लिये दोनों वर्गों के उम्मीदवारों को, कुल प्राप्त अंकों के अनुसार, पारस्परिक योग्यताक्रम में रखा जाएगा।
- (iii) उम्मीदवारों को अपने शार्टहैंड नोट टाइप करने होंगे और इसके लिये उन्हें अपनी-अपनी टाइप मशीन लानी होगी।

- परीक्षा का विषय-विवरण साथ लगी अनुसूची में दिया गया है।
 - 3. सभी प्रक्न-पत्नों के उत्तर अंग्रेजी में ही लिखे जाने चाहिएं।
- 4. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 5. आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक (क्वालीफाइंग) अंक निर्धारित कर सकता है।
- 6. केवल उन्हीं उम्मीदवारों को मार्टहैंड परीक्षा के लिये बुलाया जाएगा जो आयोग के अपने निर्णय से नियत किए गए कम-से-कम अहंक अंक प्राप्त कर लेंगे।
- 7. उम्मीदवार को प्रत्येक विषय में दिए गए अंकों में से आयोग की इच्छानुसार अंक इसलिए काट लिए जाएंगे कि कहीं कोरे सतही ज्ञान का तो कोई लिहाज नहीं रखा गया है।
- अस्पष्ट लिखावट के कारण, लिखित विषयों के अधिकतम अंकों में से, 5 प्रतिशत तक काट लिए जाएंगे।
- 9. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का विशेष लिहाज रखा जाएगा कि भाषाभिव्यक्ति आवश्यकतानुसार कम से कम शब्दों में, क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई है।

अनुसूची

परीक्षा का स्तर और विषय-षिवरण

मोट:--भाग 'क' के प्रश्न-पत्नों का स्तर लगभग वही होगा जो भारतीय विश्वविद्यालयों की मैद्रिकुलेशन परीक्षा का होता है।

अंग्रेजी: — इस प्रश्न-पत्न का प्रयोजन उम्मीदवारों के अंग्रेजी व्याकरण और निबन्ध-रचना के ज्ञान की तथा अंग्रेजी भाषा को समझने और शृद्ध अंग्रेजी लिखने की उनकी योग्यता की जांच करना है। अंक देते समय वाक्य-विन्यास, सामान्य अभिव्यक्ति और भाषा-कौशल को ध्यान में रखा जाएगा। इस प्रश्न पत्न में निबन्ध-लेखन, सार-लेखन, मसौदा-लेखन, शब्दों, आसान मुहाबरों और पूर्वसर्ग (प्रीपोजीशन) का शृद्ध प्रयोग, कर्सवाच्य और कर्मवाच्य आदि शामिल होंगे।

सामान्य ज्ञान :—-इन विषयों की थोड़ी बहुत जानकारी :
भारत का संविधान, पंचवर्षीय योजनाएं, भारतीय इतिहास
और संस्कृति, भारत का सामान्य और आर्थिक भूगोल,
सामियक घटनाएं, सामान्य विज्ञान तथा रोजाना नजर आने
वाली ऐसी बातें जिनकी जानकारी पढ़े-लिखे व्यक्ति को
होनी चाहिए । उम्मीदवारों के उत्तरों से यह प्रकट होना
चाहिए कि उन्हें प्रश्नों की अच्छी समझ है और उनका ज्ञान
किसी किताब के विस्तृत ज्ञान तक ही सीमित नहीं है।

परिशिष्ट—II

उन सेवाओं/पदों का संक्षिप्त विवरण जिनके लिए भर्ती इस परीक्षा द्वारा की जा रही है ।

क-केन्त्रीय सचिवालय आशुलिपिक (स्टेमोग्राफर) सेवा

इस समय केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निम्नलिखित दो ग्रेड हैं:—

ग्रेड I:--350-25-650 ६० (ग्रेड II से पदोन्नत व्यक्तियों को इस वेतन क्रम में कम-से-कम 400 ६० वेतन दिया जाता है)

ग्रेड II:--210-10-270-15-300 द० अ०---15-450-20-530 र०।

- PART I—SEC. 1]
- (2) सेवा के ग्रेड II में नियुक्त व्यक्ति 2 वर्ष तक परिवीका-धीन रहेंगे । इस अवधि के दौरान उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करने पड़ सकते हैं और परीक्षाएं देनी पड़ सकती
- (3) परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर सरकार सम्बन्धित व्यक्ति को उसके पद पर स्थायी रूप से नियुक्त कर सकती है या मदि उसका कार्यं सरकार की दुष्टि से संतोषजनक न रहा हो, तो, उसे सेवा से निकाला जा सकता है या उसकी परिवीक्षा की अवधि सरकार के निर्णयान्सार बढ़ाई जा सकती है।
- (4) सेवा के ग्रेड II में भर्ती व्यक्तियों को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा योजना में भाग लेने वाले मंत्रालयों या कार्यालयों में से किसी एक में नियुक्त कर दिया जायगा । किन्तू किसी भी समय उनकी किसी अन्य ऐसे मंत्रालय या कार्यालय में बदली हो सकती है।
- (5) सेवा के ग्रेड II में भर्ती व्यक्ति समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार अगले ऊंचे ग्रेड में पदोन्नत किये जा सकेंगे।
- (6) जिन लोगों की नियुक्ति उनके अपने चयन के अनुसार इस सेवा के ग्रेड f H में की जायगी, इस प्रकार की नियुक्ति के पश्चात भारतीय विदेश सेवा (ख) के काडर अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा योजना में शामिल किसी पद पर दावे या बदली के हकदार नहीं होंगे ।

च--रेलवे बोर्ड सचिवालय आझुलिपिक सेवा

- (क) जहां तक रेलवे मंत्रालय में सेवा के ग्रेड II में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति आदि का सम्बन्ध है, उनका नियमन केन्द्रीय सचिवालय आण्-लिपिक सेवा योजना के अनुरूप बनाई गई रेलवे बोर्ड सचिवालय आणुलिपिक सेवा योजना द्वारा होता है।
- (ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा योजना के निम्न दो ग्रेड हैं:--
 - (i) आणुलिपिक ग्रेड I--350-25-650 रु०
 - (ii) आणुलिपिक ग्रेड II---210--10--270--15--300 ব০ अ०−15−540 ব০ अ० 20--530 l

सीधी भर्ती केवल ग्रेड II में ही की जाती हैं। ग्रेड I के पद ग्रेड II आशुलिपिकों की पदोक्षति द्वारा भरे जाते हैं। ग्रेड II आणुलिपिकों को ग्रेड I में पदोन्नत किये जाने पर कम-से-कम 400 रु० प्रति साष्ट्र वेतन दिया जाता है।

ग्रेड I आशुलिपिकों को समय-समय पर लागू निययों के अनुसार अपने लिए नियत अध्यंश में अनुभाग अधिकारियों के पदों पर पदोन्नत करने के लिये भी विचार किया जाता है।

- (ग) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा रेलवे मंद्रालय तक सीमित है और उनके कर्मचारियों की केन्द्रीय सचिवालय आणुलिपिक सेवा की तरह अन्य मंत्राक्षयों में बदली नहीं हो सकती।
- (घ) इन नियमों के अधीन रेलवे बोर्ड सिचवालय आशुलिपिक सेवा में भर्ती अधिकारी :
 - (i) निवृत्ति वेतन सम्बन्धी लाभों के हकदार होंगे
 - (ii) अपनी नियुक्ति की तिथि पर रेलवे कर्मं चारियों पर लागू अंशदायी भविष्य निधि के नियमों के अनुसार उस निधि में राशि जमा करायेंगे।
- (ऊ) रेलवे मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारी अन्य रेलवे कर्मचारियों के समान ही पासों और रियायती टिकटों के हकदार होंगे।

(च) अहां तक छुट्टी तथा सेवा की अन्य शतीं का सम्बन्ध है, रेलवे बोर्ड सचिवानय आशुलिपिक सेवा में शामिल कर्मचारियों के साथ वहीं व्यवहार होगा जो रेलवे के अन्य कर्मचारियों के साथ होता है किन्तु चिकित्सा सुविधाओं के बारे में उन पर नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में नियुक्त केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मनारियों पर लागु होने बाले नियम ही लागू होंगे।

ग---भारतीय विवेश सेवा (ख) आशुलिपिकों के उप-संवर्ग का

भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक उप-संवर्ग का बेतन क्रम 210-10-270-15-300 द० अ० 15-450 द० अ० 20-530 रु० है। भारतीय विदेश सेवा (ख) के उप संवर्ग दो में नियुक्त अधिकारियों पर, भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' (आर० सी० एस० पी०) नियम 1964 तथा भारतीय विदेश सेवा (पीठ एल० सी० ए०) नियम, 1961 जैसे कि बे भारतीय विदेश सेवा 'ख' पर लागू होते हैं तथा अन्य ऐसे नियम जो भारत सरकार द्वारा उन पर लगाए जायं, लागू होंगे।

भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' विदेश मंत्रालय तथा विदेशों में स्थित भारतीय आयोगों तक ही सीमित है और इस सेवा में नियुक्त अधिकारियों की बदली आम तौर पर वाणिज्य मंत्रालय के अतिरिक्त अन्य मंत्रालयों में नहीं की जा सकती। हां वे भारत में या भारत से बाहर कहीं भी सेवा पर नियुक्त किये जा सकते हैं ।

विदेश में सेवा के दौरान भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधि-कारियों को अपने आधारभूत वेतन के अलावा सम्बन्धित देश के जीवन-मान के आधार पर समय-समय पर निर्धारित दर से विदेश भत्ता भी दिया जाता है इसके अलावा भारतीय विदेश सेवा (ख) (पी० एल० सी० ए०) नियम, 1961 जैसे कि वे भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारियों पर लाग होते हैं—के अनुसार उन्हें विदेश में सेवा के दौरान निम्नलिखित रियायर्ते भी दी जाती हैं:---

- (i) भरकार द्वारा निर्धारित स्तर के अनुसार निःशुल्क उपस्कृत आवास ।
- (ii) सहायित चिकित्सा योजना के अर्धान चिकित्सा मुविधाएं ।
- (iii) कुछ भती के अर्धान 8 से 18 वर्ष तक की आयु के भारत में शिक्षा पाने वाले बच्चों को वर्ष में एक बार लर्म्बा छुट्टियों के दौरान माना पिता से मिलने के लिये वापसी हवाई थाना ।
- (iv) समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर 5 से 18 वर्ष तक की आयु के अधिक से अधिक दो बच्चों के लिये शिक्षा भत्ता ।
- (v) समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित निययों और दरों के अनुसार विदेश में सेवा के लिये सज्जा भत्ता । जिन अधिकारियों की नियुक्ति ऐसे देशों में की जाती है जहां अशामान्य रूप से भीत पड़ता है, उन्हें सामान्य मज्जा भत्ते के अलावा विशेष सज्जा भत्ता भी दिया जाता है।
- (vi) विहित नियमों के अनुगार अधिकारियों तथा उनके परिवार के लिये छुट्टी में घर आने-जाने की याला ।

सेवा के सदस्यों पर कुछ संगोधनों के साथ 1933 के संगोधित अवकाण नियमों का समय-समय पर संगोधित रूप लागू होगा। कुछ पडौर्सा देशों को छोड़ कर विदेशों में सेवा के लिये अधिकारियों को संशोधित अवकाश नियमों के अधीन स्वीकृत अवधि से 50 प्रतिशत तक अधिक अतिरिक्त अवकाश जमा करने का हक होगा ।

भारत में रहते हुए अपने समान तथा वैसे ही स्तर के अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के समान रियायर्ते मिल सकेंगी।

भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारियों पर सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियम 1960 का समय-समय पर संशोधित रूप तथा उसके अधीन जारी किये जाने वाले आदेश लागू होते हैं।

इस सेवा में नियुक्त अधिकारियों पर उदार निवृत्तिवेतन नियम, 1950 के समय-समय पर संशोधित रूप तथा उनके अधीन जारी किये जाने वाले आदेश लागू होंगे।

ध--चुनाव आयोग, भारत

चुनाव आयोग में आशुलिपिकों के पदों का वेतन कम केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के समान ही 210-10-270-15-द० अ० 300-द० अ०-15-450-द०-अ०-20-530 र० होगा। किन्तु येपद केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा योजना में शामिल नहीं हैं और इन पदों पर नियुक्त व्यक्ति का केन्द्रीय सचिवालय सेवा में सम्मिलित पदों पर नियुक्ति के लिये कोई हक नहीं होगा।

इ--पर्यटन विभाग

पर्यटन विभाग में वरिष्ठ आणुलिपिकों के पद 210-10-290-15-320 द० अ० 15-425 के संशोधित वेतन कम में स्विकृत हैं और सामान्य केन्द्रीय सेवा (श्रेणी II) (अराजपितत) मंत्रालियक से सम्बन्धित हैं । कम से कम 5 वर्ष की सेवा वाले गरिष्ठ आणुलिपिक वैयम्तिक सहायकों के पद पर नियुक्ति के हक्तवार होते हैं जिनका वेतन कम 320-15-470 द० अ० 15-530 र० है। इस पर्का के परिणामों के आधार पर नियुक्ति उम्मीदवारों को आम तौर पर विभाग के मुख्यालय में कार्य करना होता है किन्तु उन्हें भारत में कहीं भी नियुक्त किया जा सकता है।

(च) सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक संवर्ग

सशस्त्र सेना मुख्यालय आणुलिपिक मंवर्ग में आशुलिपिक ग्रेड II के पद अराजपितित (श्रेणी III) अस्थायी हैं। यह संवर्ग सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा अन्तर्सेवा संगठनों तक सीमित है। इस समय इस संवर्ग में निम्नलिखित दो ग्रेड हैं:——

आशुलिपिक ग्रेड I-375-12-575-25-600 रु० आशुलिपिक ग्रेड II--210-10-270-15-300-द० अ०-15-450-द० अ० 20-530।

- 2. अस्थायी आणुलिपिक ग्रेड II में सीधे भर्ती होने वाले व्यक्ति 2 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे। इस अवधि में सेवा के असंतोषजनक रिकार्ड के परिणाम स्वरूप परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवा से निकाला भी जा सकता है।
- 3. सशस्त्र सेना मृख्यालय में भर्ती आणुलिपिक ग्रेड II अधिकारी आमतौर पर दिल्ली स्थित तीन सेवा मुख्यालयों/अन्तर्सेवा संगठनों में नियुक्त किये जायेंगे। किन्तु उनकी बदली दिल्ली/नई दिल्ली से बाहर ऐसे नगरों में भी की जा सकेगी जहां सशस्त्र सेना मुख्यालय अंतर्सेवा संगठनों के कार्यालय स्थित हों।
- 4. आशुलिपिक ग्रेड II समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार आशुलिपिक ग्रेड I के पदों पर पदोन्निति के हकदार होंगे ।
- 5. अवकाश, चिकित्सा सहायता तथा सेवा की अन्य शर्ते वहीं हैं जो सशस्त्र सेना मुख्यालय में नियुक्त अन्य मंत्रालयिक कर्मचारियों पर लागू होती हैं।

(छ) संसदीय मामलों का विभाग

इस विभाग में आश्लिपिकों के पदों का वेतन कम 210-10-270-15-300—द० अ०-15-450—द० अ०-20-530 र० है।

इस प्रतियोगिता परीक्षा के जरिये चुनाव द्वारा सेवा में नियुक्त जर्म्माववारों को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन रखा जायगा ।

वाणिस्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 सितम्बर 1965

सं० 29(1) प्लांट० (बीं०)/62—इस मन्त्रालय की इसी सं० की अधिसूचना दिनांक 18 सितम्बर 1965 के सम्बन्ध में एतत् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि इलायची विकास और विपणन सलाहकार समिति के वर्तमान अध्यक्ष तथा सदस्य 2, नकम्बर 1965 से 2 महीने की अविधि तक के लिए अपने पद पर और बने रहेंगे।

एस० बनर्जी, उप-सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 21 अक्तूबर 1965

सं० 12/18/65-ई० प्रापर०—भारत रक्षा नियम, 1962 के नियम 133 बी० के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करती हुई केन्द्रीय सरकार सहर्ष आदेश देती है कि में० विकटर जूट प्राडक्टस लि० 51 इजरा स्ट्रीट, कलकत्ता की भारत में समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति जो कि उनकी है, जो उनके पास है या जिसका प्रबन्ध उनकी और से किया जाता है भारत शत्नु सम्पत्ति परिरक्षक के अधिकार में चली जाएगी।

सं० 12/19/65-ई० प्रापर०—भारत रक्षा नियम, 1962 के नियम 133 बी० के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करती हुई केन्द्रीय सरकार सहर्ष आदेश देती है कि में० दी फीस्कूल स्ट्रीट प्रापरटी लि०, 51, इजरा स्ट्रीट, कलकत्ता की भारत में समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति जो कि उनकी है, उनके पास है या जिसका प्रबन्ध उनकी ओर से किया जाता है भारत शक्ष सम्पत्ति परिरक्षक के अधिकार में चली जाएगी।

पीं० के॰ जे॰ मेनन, संयुक्त सचिव

पेट्रोकियम और रसायन मंत्रासप

संकरूप

नई दिल्ली, दिनांक 1 अक्तूबर 1965

सं० सी० एच०/कोआरडी०/4/65—भारत सरकार में रसायन और उर्वरक उद्योगों से सम्बन्धित सामान्य हित की समस्याओं पर सरकार को सलाह देने के लिए एक समिति की स्थापना करने का फैसला किया है, जो रसायनों की केन्द्रीय सलाह-कार समिति कहलायेगी । इस समिति के निम्न सदस्य होंगे :—

- (1) मन्त्री (पैट्रोलियम और रसायन)-अध्यक्ष
- (2) पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री— उपाष्ट्रयक्ष
- (3) श्री के० पी० विपाठी, उद्योग मंत्री, असम सरकार, शिलांग ।
- (4) डा० एस० डी० शर्मा, उद्योग मंती, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल ।
- (5) डा॰ जी॰ एस॰ मेलकोटे, संसद् सदस्य, 18, जनपथ, नई दिल्ली ।
- (6) श्री । संतोष सिंह,
 संसद् सदस्य,
 154/48, चाणक्य पुरी, नई दिल्ली ।
- (7) श्री एम० आर० शेरवानी, संसद सदस्य, 11, सुन्दर नगर, नई दिल्ली।

- (8) श्री के० सी० पन्त, संसद सदस्य, सी० 1/35, पण्डारा रोड, नई दिल्ली ।
- (9) श्री पी० डी० हिमत सिंधका, संसद सदस्य, 68, साऊथ एवेन्यू, नई दिल्ली ।
- (10) डा॰ एन॰ आर॰ नानजी, मेहर हाऊस, 15,कोआस जी पटेल स्ट्रीट,फोर्ट, बम्बई-1।
- (11) श्री सी० पी० जवेरी, प्रधान, फारमिस्युटीकल एण्ड एलाईड मैनुफैक्चेज एण्ड डिस्ट्रीब्यूटरज एस्सोसीयेशन लि०,

मार्फत

गम्बई चैम्बर्ज आफ कामर्स एण्ड सप्लाई, मैकिनोन मकेनजी विल्डिंग, बलार्ड अस्टेट, बम्बई-1।

- (12) श्री चरत राम, दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिलज को० लि०,बारा हिन्दू राव, दिल्ली-6।
- (13) श्री सी० एल० गुप्ता,
 मार्फत
 इण्डियन प्लास्टिक फैंडरेशन,
 रघुवंशी बिल्डिंग,
 तीसरी मंजल, कमरा नं० 57,
 134/1, महात्मा गांधी रोड, कलकत्ता-7 ।
- (14) डा॰ जे॰ एस॰ बादामी,
 प्रधान, इण्डियन सोप एण्ड टायलिट्रीज,
 मेकर्ज एस्सोसीयेशन,
 पी॰-11, मिशन रोड एक्सटैन्शन, कलकत्ता-1 ।
- (15) लाला बन्सी धर, प्रधान, आल इण्डिया डिस्टिल्लरीज एस्सोसीयेशन, एच०-37, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-1।
- . (16) श्री प्रेम चन्द जैन, धारांगधरा कैमीकल सर्कस लि० 15 ए०, हारनीमन सर्किल, फोर्ट, बम्बई-1।
 - (17) श्री आर० बी० अमीन, चैयरमैन, अलम्बिक कैमीकल वर्क्स को० लि०, बरौदा ।
 - (18) श्री के० के० बिरला, इण्डिया एक्सचैंज प्लेस, कलकत्ता ।
 - (19) श्री एल० साहनी,
 टाटा कैमीकलज,
 बम्बई हाऊस, ब्रूस स्ट्रीट, फोर्ट,
 बम्बई-1।
 - (20) श्री एच० के० एस० लिण्डसे,
 प्रधान, एस्सोसियेटिड चैम्बर्ज आफ कामसं एण्ड
 दण्डस्ट्री आफ इण्डिया, रायल एक्सचेंज,
 6, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता ।
- (21) श्री बी॰ सी॰ मुखर्जी,
 चेयरमैन एण्ड प्रबन्ध निदेशक,
 फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि॰, एफ॰43, नई दिल्ली साऊय एक्सटैन्शन, पोर्ट-1
 नई दिल्ली-3।

- (22) श्री टी॰ एस॰ नारायण स्वामी,
 कैमीकरुज एण्ड प्लास्टिक्स इण्डिया लि॰,
 धून बिल्डिगँ, 175/1, माउण्ट रोड,
 मद्रास-2 ।
- (23) डा॰ ए॰ रामास्वामी मुदलीयर, इण्डिया स्टीमणिप हाऊस, 21, ओल्ड कोर्ट हाऊस स्ट्रीट, कलकत्ता-1 ।
- (24) श्री अरिवन्द मफललाल, मफत लाल हाऊस, बक बेरिक्लेमेशन, बम्बई-1 ।
- (25) श्री जे० के० जौन, पैरी एण्ड को०, लि०, पोस्ट बाक्स नं० 12, मद्रास-1 ।
- (26) श्री ए० हुसैन, 113 ई०, रिपन स्ट्रीट, कलकत्ता-16 ।
- (27) श्री कादिर कुट्टी, इण्डिस्ट्रयलिस्ट, तिल्लीचेरी (केरल) ।
- (28) श्री कल्याण सेन,
 मैसर्ज एलाइड रैसीना एण्ड
 कैमीकलज (पी०) लि०,
 10-1, एसगिन रोड,
 कलकत्ता-20 ।

 U. रसायनों की सलाहकार समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे :---

- (क) रसायन उद्योगों से सम्बन्धित सामान्य-हित के विषयों पर विशेष रूप से रसायनों के इस्तेमाल एवं विकास के आयोजन और रसायन उद्योगों से युक्त प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में सरकार को सलाह देना ।
- (ख) सामान्यरूप से रसायनों की मांग, सप्लाई और वितरण के प्रतिरूप का अध्ययन एवं परामर्श देना ।
- (ग) रसायन उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में पेश आने वाली समस्याओं का अध्ययन और उन समस्याओं के हल का सुझाव देना ।
- (व) सामान्य रूप से रसायन उद्योगों की भविष्य स्थिति एवं स्थापना पर सलाह देना ।
- (ङ) रसायन उद्योगों में उत्पादन की वृद्धि के लिए उपायों का सुझाव देना ।
- (च) रसायन उद्योगों में मूल्य स्तर पर काबू पाने के उपायों पर विचार करना तथा सलाह देना ।
- (छ) कोई अन्य विषय जो उसे विशेषतः दी जाये । III. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शामिल करते हुए समिति के 30 सदस्य होंगे ।
- IV. समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिये अध्यक्ष किसी अन्य व्यक्ति को भी जो सदस्य न हो विशेष रूप से निमन्त्रित कर सकता है।

V. एक साल में समिति सामान्यतः दो बार इकट्ठी होगी। अध्यक्ष को यदि वह आवश्यक समझे, एक विशेष बैठक बुलाने की शक्ति दी गई है। सदस्यों की नियुक्ति की अविधि दो सालों के लिए होगी।

VI. रसायन विभाग द्वारा सिचवालय सम्बन्धी सहायता की व्यवस्था होगी ।

आहेग

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की, एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, सभी राज्य सरकारों, प्रधान मंत्री के सिचवालय, मंत्रिमण्डल के सिचवालय, संसद सिचवालय, राष्ट्रपति के निजी और सैनिक सिचवों, योजना आयोग, भारत सरकार के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक, महा लेखाकार-केन्द्रीय राजस्व, वाणिज्य, निर्माण तथा विविध के महालेखाकार को भजी जाती है।

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प की एक प्रति आम सूचना के लिए भारतीय राजपक्ष में भी प्रकाशित की जाए।

नकुल सैन, सचिव

उद्योग सथा सम्भरण मंत्रालय (उद्योग विमाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 अक्तूबर 1965

सं० 9/2/65-साल्ट—भूतपूर्व वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के संकल्प सं० 9/2/65-साल्ट, तारीख 9 अप्रैल 1963 के अधिलंघन में भारत सरकार ने नमक के केन्द्रीय एवं प्रादेशिक सलाहकार बोर्डों का पुनर्गठन करने का निष्चय किया है। केन्द्रीय बोर्ड के कार्य नमक उप-कर अधिनियम, 1953 की घारा 3 के अधीन लगाये गये नमक उप-कर की आय के प्रशासन पर भारत सरकार को सलाह देना तथा नमक उद्योग का विकास करने के लिए उपयुक्त उपायों के बारे में सामान्य रूप से सिफारिशें करना होंगे उदाहरणत: —

- (1) अनुसन्धान केन्द्रों. आदर्श फार्मों तथा नमक कारखानों की स्थापना और उनकी देख-रेख करना;
- (2) नमक के वर्ग निश्चित करना और उसकी किस्म में सुधार करना;
- (3) निर्यात का विकास करना;
- (4) नमक निर्माताओं में सहकारी प्रयत्नों को बढ़ावा देना और प्रोत्साहन देना;
- (5) नमक उद्योग में लगे श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देना; और
- (6) किसी भी अन्य मामले में जो सामान्य रूप से तमक उद्योग के विकास से सम्बन्ध रखता हो ।

प्रादेशिक बोर्डी का काम इन्हीं आधार पर जहां तक उनके सम्बन्धित क्षेत्रों का सम्बन्ध है, केन्द्रीय बोर्ड से सिफारिश करना होगा ।

2. पुनर्गठित केन्द्रीय तथा प्रादेशिक बोडों की रचना निम्न प्रकार होगी :--

(क) सामान्य सलाहकार बोर्ड

अध्यक्ष

 विशेष कार्य-अधिकारी, उद्योग तथा संभरण मंद्रालय, 'नमक' के प्रशासन से सम्बन्धित ।

सदस्य

- उप सचिव, उद्योग तथा संभरण मंत्रालय, 'नमक' के प्रशासन से सम्बन्धित।
- 3 वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ।
- 4. प्रभारी उप-निर्देशक, सेन्द्रल सान्ट एण्ड मेरीन केमिकल्स रिसर्च इन्स्टीट्यूट, भावनगर ।
- उप-महा-निदेशक, तकनीकी विकास का महा-निदेशालय, उद्योग तथा संभरण मंत्रालय, नई दिल्ली ।
- 6-7. मद्रास, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के प्रमुख नमक उत्पादक राज्यों की सरकारों से दो

प्रतिनिधि जिनका नामांकन केन्द्रीय सरकार द्वारा बारी-बारी से किया जायेगा । वर्तमान बोर्ड की अवधि में राजस्थान और महाराष्ट्र की सरकारों का एक-एक प्रतिनिधि होगा ।

- 8-9. ऋम संख्या 6 और 7 में ऊपर उल्लिखित राज्यों के अतिरिक्त राज्यों की सरकारों के दो और प्रतिनिधि होंगे जिनका नाम-निर्देशन केन्द्रीय सरकार द्वारा बारी-बारी से किया जाएगा । वर्तमान बोर्ड की अविधि में आसाम और उत्तर प्रदेश की सरकारों का एक-एक प्रतिनिधि रहेगा ।
- 10·14. केन्द्रीय सरकार द्वारा (1) मद्रास, (2) आन्ध्र प्रदेश, (3) पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा, (4) महाराष्ट्र और (5) गुजरात राज्यों से एक-एक प्रतिनिधि का नाम-निर्देशन किया जाएगा, जिसे, उसकी सम्मति में, उस क्षेत्र में नमक के निर्माण का ज्ञान और अनुभव प्राप्त है, नामन:—
 - (1) श्री एम० एम० गुरुनाथ, 3, लक्ष्मण चेट्टियार स्ट्रीट, टीं० नगर, मद्रास-17 ।
 - (2) श्री ए० सूर्यनारायण राव, अपना हाउस, विशाखापत्तनम-1 ।
 - (3) श्री एम० यूसुफ,
 द्वारा मेसर्स उड़ीसा साल्ट मैन्यूफैक्चरर्स एसोसियेशन,
 कटक ।
 - (4) श्रीः जयन्ती लाल विभवनदास, चेयरमैन, बम्बई साल्ट मचेंट्स एसोसियेशन, जम्बली नाका, थाना, **बम्बई**।
 - (5) श्री एस० एम० अन्तानी, द्वारा कच्छ साल्ट एण्ड एलाइड इन्ड०, कोडला (गुजरात)।
 - 15. केन्द्रीय सरकार द्वारा एक ऐसे व्यक्ति का नाम-निर्देशन किया जाना है, जिसे, उसकी सम्मिति में, नमक व्यापार का ज्ञान और अनुभव है, नामत:—-

श्री श्रीनिवास फतहपुरिया, ब्रारा मेसर्स जमनादास श्रीनिवास (प्रा०) लि०, 82/2 मुकुटराम बाबू स्ट्रीट, कलकत्ता-7 ।

- 16-17. केन्द्रीय सरकार द्वारा दो ऐसे व्यक्तियों का नाम-निर्देशन किया जाना है, जिन्हें उसकी सम्मति में, सार्वजनिक कार्यों का शान और अनुभव है, नामत:—-
 - श्री जी० एल० ओजा, संसद सदस्य, वात्सल्य विद्यानगर, राजकोट-2 ।
 - (2) श्री एम० तिरुमल राव, संसद सदस्य, गोधीनगर,

काकिनाडा (आन्ध्र प्रदेश) ।

18. केन्द्रीय सरकार द्वारा एक ऐसे व्यक्ति का नाम-निर्देशन किया जाना है, जिसे, उसकी सम्मति में, श्रम-समस्याओं का ज्ञान और अनुभव है:—

नाम की घोषणा शाद में की जाएगी।

19. केन्द्रीय मरकार द्वारा एक ऐसे व्यक्ति का नाम-निर्देशन किया जाना है, जिसे, उसकी सम्मति में, नमक पर आधारित रसायनिक उद्योगों का ज्ञान और अनुभव है, नामत:---

श्री डी० एम० सेठ, द्वारा मेसर्स टाटा केमिकल्स लि०, बम्बई हाउस फोर्ट,

बम्बई-1।

20. केन्द्रीय सरकार द्वारा एक ऐसे व्यक्ति का नाम-निर्देशन किया जाना है, जिसे, उसकी सम्मति में नमक का निर्माण करने वाली सहकारी समिलियों के कार्यी का ज्ञान और अनुभव है, नामन:—

श्री त्रम्बक लाल जे० शुक्ल, चेयरमैन श्री गुजरात राज्य मीठा उद्योग सहकारी संघ लि०, दारासर रोड, सुरेन्द्रनगर (गुजरात) ।

सबस्य-सचिव

21. नमक आयुक्त ।

टिप्पणी:—रेलवे मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, राज्य व्यापार निगम तथा वाणिज्य मंत्रालय, का 'निर्यात संवर्धन' स्कन्ध के प्रतिनिधियों को, यथावण्यक, केन्द्रीय सलाहकारी बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिये आवंत्रित किया जा सकता है।

(ख) प्रावेशिक सलाहकार बोर्ड

1. मद्रास

अध्यक्ष

1. नमक आयुक्त ।

सवस्य

- 2. मद्रास सरकार का एक प्रतिनिधि।
- 3-4. केन्द्रीय सरकार द्वारा दो ऐसे व्यक्तियों का नाम-निर्देशन किया जाना है, जिन्हें उसकी सम्मति में, श्रम-समस्याओं का ज्ञान और अनुभव प्राप्त है :—
 - $\binom{1}{2}$ नामों की घोषणा बाद में की जाएगी।
- 5-6. केन्द्रीय सरकार द्वारा दो ऐसे व्यक्तियों का नाम-निर्देशन किया जाना है, जिन्हें उसकी सम्मति में उस् क्षेत्र में नमक का निर्माण करने का जान और अनुभव है, नामत:—
 - (1) श्री सी० आई० आर० मछाडो, फातिमा लाज, 9, मनाल स्ट्रीट, तूतीकोरीन-1 ।
 - (2) श्री पी० लक्ष्मी नारायण नायडू, 397, टी० एच० रोड,

मद्रास-21 t

- 7-8. केन्द्रीय सरकार द्वारा दो ऐसे व्यक्तियों का नाम-निर्देशन किया जाना है, पिन्हें, उसकी सम्मित में सार्वजनिक कार्यों का ज्ञान और अनुभव है, नामत:—
 - (1) डा॰ पी॰ श्रीनिवासन, संसद सदस्य, 4 बी॰ रत्नसभापति मुदलियार रोड, महास-21 ।
 - (2) श्री वैरव थेवर, संसद सदस्य (लोक-सभा) कुँडामराइ काडू,

ग्राम कुरुविक्कमबई, डाक और जिला—थंजावुर (मद्रास) ।

सवस्य-सन्तिव

- 9. उप नमक आयुक्त, मद्रास ।
- 2. आग्ध्र प्रदेश

अध्यक्ष

1. नमक आयुक्त

सवस्य

- 2. आन्ध्र प्रदेश सरकार का एक प्रतिनिधि ।
- 3-4. केन्द्रीय सरकार द्वारा दो ऐसे व्यक्तियों का नाम-निर्देशन किया जाना है, जिन्हें, उसकी सम्मति में, श्रम-समस्याओं का ज्ञान और अनुभव है:---
 - $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ नामों की घोषणा बाद में की जाएगी।
- 5-6. केन्द्रीय सरकार द्वारा दो ऐसे व्यक्तियों का नाम-निर्देशन किया जाना है, जिन्हें, उसकी सम्मति में, उस क्षेत्र में नमक के निर्माण का ज्ञान और अनुभव है, नामतः—
 - (1) श्री ए० सूर्यनारायण मूर्ति,
 अप्पन्ना हाउम,
 विशाखायत्तनम-1 (आन्ध्र प्रदेश) ।
 - (2) श्री पी० चन्द्रशेखर रेड्डी, प्रमुख अनुज्ञप्तिधारी, इस्कापल्ली फैक्ट्री, अल्लूर पोस्ट, जिला नेल्लोर ।
- 7-8. केन्द्रीय सरकार द्वारा दो ऐसे व्यक्तियों का नाम-निर्देशन किया जाना है, जिन्हें उसकी सम्मित में, सार्वजनिक कार्यों, का ज्ञान और अनुभव है, नामत:——
 - (1) श्री एम० एस० मूर्ति, संसद सदस्य, डाकघर कोंडाकरिया अनकापस्ले होकर, जिला विशाखापत्तनम (आन्ध्र प्रदेश)।
 - (2) श्री बी० राजगोपाल राव, समद सदस्य, डाकघर—अमदलावालसा, जिला—श्री काकुलम आग्ध्र प्रदेश।

सदस्य-सचिव

- 9. उप नमक आयुक्त, मद्रास ।
- 3. पश्चिमी बंगास तथा उद्दीसा

अध्यक्ष

1. नमक आयुक्त ।

ें सबस्य

- 2.3. पश्चिमी बंगाल तथा उड़ीमा की सरकारों का एक-एक प्रतिनिधि ।
- 4-5. केन्द्रीय सरकार द्वारा दो ऐसे व्यक्तियों का नाम-निर्देशन किया जाना है, जिन्हें, उसकी सम्मति में, श्रम-समस्याओं का ज्ञान और अनुभव है:—
 - $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ नामों की घोषणा बाद में की जाएगी ।

- 6-7. केन्द्रीय सरकार द्वारा दो ऐसे व्यक्तियों का नाम-निर्देशन किया जाना है, जिन्हें उसकी सम्मति में, उस क्षेत्र में नमक का निर्माण करने का ज्ञान और अनुभव है, नामतः
 - (1) श्री सर्वतोष बेरा, निदेशक, ग्रेट बंगाल साल्ट कम्पनी लि० ।
 - (2) श्री टी० शिवरामय्या, जपाध्यक्ष, दि हुम्मा साल्ट प्रोडक्शन सेल्स कोआपरेटिक सोसाइटी लिमिटेड, डाकघर तथा जिला गंजम, उड़ीसा ।
- 8-10. केन्द्रीय सरकार द्वारा तीन ऐसे व्यक्तियों का नाम-निर्देशन किया जाना है, जिन्हें उसकी सम्मति में, सार्वजनिक कार्यों का ज्ञान और अनुभव है, नामतः—
 - (1) श्री एस० सी० सामन्त संसद सदस्य, डाकघर और ग्राम-तामलुक, जिला----मिदनापुर, पश्चिमी बंगाल
 - (2) श्री करुणाकर पाणिग्रही, विधान-सभा सदस्य, भुवनेश्वर।
 - (3) श्रीमती इला पाल नौधरी,64, लेक प्लेस,कलकत्ता-29 ।

सदस्य-सचिव

11. सहायक नमक आयुक्त, कलकत्ता ।

4. महाराष्ट्र

अध्यक्ष

1. नमक आयुक्त ।

सदस्य

- 2. महाराष्ट्र सरकार का एक प्रतिनिधि।
- 3-4. केन्द्रीय सरकार द्वारा दो ऐसे व्यक्तियों का नाम-निर्देशन किया जाना है, जिन्हें, उसकी सम्मित में भ्रम-समस्याओं का ज्ञान और अनुभव है :---
 - (1) श्री एस० जी० कार्णिक, मीठाधर कामगर यूनियन, 115, सत्यगिरि दादर मेन रोड, बादर, बस्बई-14 ।
 - (2) श्री आर० बी० पाटिल, मीठाघर कामगर यूनियन, 115, सत्यगिरि, दादर मेन रोड,

सम्बई-14 ।

- 5-6. केन्द्रीय सरकार द्वारा दो ऐसे व्यक्तियों का नाम-निर्देशन किया जाना है, जिन्हें उस क्षेत्र में नमक के निर्माण का ज्ञान और अनुभव है, नामतः—
 - (1) श्री एमे० ए० भाईजी, उप-प्रधान, अर्बन साल्ट मर्चेन्ट्स एण्ड शिलहोटरीज सिण्डीकेट, उरान ।

(2) नादिरशाह फीरोजशाह बरथानियां, द्वारा नादिरशाह फीरोजशाह एण्ड कं०, स्टेट बैंक के ऊपर, अब्दुल रहमान स्ट्रीट,

बम्बई ।

- 7-8. केन्द्रीय सरकार द्वारा दो ऐसे व्यक्तियों का नाम-निर्देशन किया जाना है, जिन्हें सार्वजनिक कार्यों का श्वान और अनुभव है, नामत:—
 - (1) श्री एन० एस० काजरोलकर, संसद सदस्य,
 185, डा० अम्बेदकर रोड, परेल,
 बम्बई-12 ।
 - (2) श्री शंकर बाबाजी सावन्त, विधान सभा सदस्य, काकरतले, डाकघर—महाद, जिला—कोलाबा, महाराष्ट्र राज्य
- गोआ, दमन और ड्यू सरकार, पंजिम के उद्योग निदेशक।

सवस्य-सचिव

10. उप-नमक आयुक्त, बम्बई ।

5. गुजरात

अध्यक्ष

नमक आयुक्त ।

सबस्य

- 2. गुजरात सरकार का एक प्रतिनिधि ।
- 3-4. केन्द्रीय सरकार द्वारा दो ऐसे व्यक्तियों का नाम-निदशन किया जाना है, जिन्हें उसकी सम्मति में, श्रम-समस्याओं का ज्ञान और अनुभव है :—

 $\begin{pmatrix} \\ \\ \\ \end{pmatrix}$ नामों की घोषणा बाद में की जाएगी ।

- 5-6. केन्द्रीय सरकार द्वारा दो ऐसे व्यक्तियों का नाम-निर्देशन किया जाना है, जिन्हें, उसकी सम्मित में, उस क्षेत्र में नमक के निर्माण का ज्ञान और अनुभव है, नामत:—
 - (1) श्री बी० आर० कामदार, अध्यक्ष, सौराष्ट्र एण्ड कच्छ साल्ट मैन्यूफैक्जरसं एसोसियेशन, जामनगर।
 - (2) श्री कल्याण भाई टी० शाह, द्वारा गुजरात व्यापारी महामण्डल, पो० आ० नं० 162, अहमवाबाव।
- 7-8 केन्द्रीय सरकार द्वारा दो ऐसे व्यक्तियों का नाम-निर्देशन किया जाना है, जिन्हें, उसकी सम्मति में सार्वजनिक कार्यों का ज्ञान और अनुभव है, नामत:—
 - (1) श्री एम० बी० वैश्य, संसद सदस्य, 17, सुतिरिया सीसाइटी, शाहपुर गेट के बाहर, अहमदाबाद।

- (2) श्री टी॰ एम॰ वाबे, विभान-सभा सदस्य, खंडी,पोल, विधवां सिटी, जिला—सुरेन्द्रनगर, गुजरात राज्य
- गोआ, दमन और इ्यू सरकार पंजिम के उद्योग निदेशक।

सदस्य-सचिव

10. उप-नमक आयुक्त, अम्बई ।

6. राजस्थान

अध्य**क्ष**

1. नमक आयुक्त ।

सदस्य

- राजस्थान सरकार का एक प्रतिनिधि ।
- 3-4. केन्द्रीय सरकार द्वारा दो ऐसे व्यक्तियों का नाम-निर्देशन किया जाना है, जिन्हें, उसकी सम्मति में श्रम-समस्याओं का ज्ञान और अनुभव है:---
 - (1) नामों की घोषणा बाद में की जाएगी। (2)
- 5-6. केन्द्रीय सरकार द्वारा दो ऐसे व्यक्तियों का नाम-निर्देशन करना जिन्हें, उसकी सम्मति में, उस क्षेत्र में नमक के निर्माण का ज्ञान और अनुभव है, नामत:——
 - (1) जनरल मैंनेजर, राजस्थान गवर्नमेंट साल्ट मोर्सेज, जयपुर
 - (2) श्री गोपी कृष्ण टोटला, राजस्थान साल्ट इण्डस्ट्रीज, सांमर शील (राजस्थान) ।
- 7-8. केन्द्रीय सरकार द्वारा दो ऐसे व्यक्तियों का नाम-निर्देशन किया जाना है, जिन्हें उसकी सम्मति में, सार्वजनिक कार्यों का ज्ञान और अनुभव है, नामतः---
 - (1) श्री जसवन्त राय मेहता, संसद सदस्य, लाधन् हाउस, **जोघपर**
 - (2) श्री मोती लाल चौधरी, विधान-सभा सदस्य,

श्रीववाना ।

सबस्य-सचिव

- उप-नमक आयुक्त (मुख्यालय),
 कयपुर ।
- 3. (क) केन्द्रीय एवं प्रादेशिक सलाहकार बोर्डों की अवधि उनके निर्माण की तारीख से दो वर्षों की होगी।
- (ख) यदि किसी बोर्ड का कोई गैर-सरकारी स्थान रिक्त हो जाता है तो केन्द्रीय सरकार उस रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए नया नाम-निर्देशन करेगी। इस प्रकार नाम-निर्देशित व्यक्ति बोर्ड की अवधि के असमाप्त अंग तक उस स्थान पर कार्य करेगा।
- (ग) यवि नाम-निर्देशित सदस्य निसी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है, तो वह केन्द्रीय अथवा प्रादेशिक बोर्ड के अध्यक्ष, जैसी भी दशा हो, को यह तथ्य लिखित रूप से सूचित करेगा।
- (घ) पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के प्रादेशिक बोर्ड के अतिरिक्त, जिसके लिये कोरम 4 होगा, केन्द्रीय बोर्ड के लिये 7 एवं प्रादेशिक बोर्डी के लिये बैठक का कोरम 3 होगा।

- (इ) बोडं की सिफारिश पर यथोचित रूप से गठित केन्द्रीय या प्रादेशिक बोर्ड अवना उप-समिति की बैठक में भाग लेने बाला प्रत्येक गैर-सरकारी सदस्य नियमों के अन्तर्गत अथना समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता/पाने का अधिकारी होगा। प्रादेशिक बोर्डों के वे सदस्य जो संसद सदस्य हैं केन्द्रीय बोर्ड की बैठकों में भाग ले सकते हैं तथा केन्द्रीय बोर्ड के सदस्य, जिन्हें किसी क्षेत्र विशेष में नमक के निर्माण का ज्ञान और अनुभव है, उस क्षेत्र के प्रादेशिक बोर्ड की बैठकों में भाग ले सकते हैं।
- (च) कोई भी गैर-सरकारी सदस्य केन्द्रीय अथवा प्रादेशिक बोर्ड, जसी भी दणा हो, के अध्यक्ष को पत्न सम्बोधित कर अपने पद से त्यागपत्न दे सकता है।
- (छ) यदि कोई गैर-सरकारी सदस्य भारत छोड़ देता है, तो भारत छोड़ने से पूर्व वह संबंधित बोर्ड के अध्यक्ष को अपने जाने की तारीख तथा भारत वापस लौटने की सम्भावित तारीख के बारे में सूचित करेगा और यदि उसका विचार भारत से छः मास से अधिक अवधि तक बाहर रहने का है तो वह अपना त्यागपन्न दे देगा। यदि ऐसा कोई सदस्य उपर्युक्त का पालन किये बिना भारत छोड़ देता है तो उसे भारत छोड़ने की तारीख से त्यागपन्न दिया हुआ समझा जायेगा।
- (ज) संबंधित अध्यक्ष द्वारा कोई भी सदस्य अपने पद को खाली किया घोषित किया जायेगा,
 - (।) यदि वह दिवालिया हो जाता है, अथवा
 - (2) यदि उस पर किसी ऐसे अपराध के लिये अभियोग चलाया जाता है, जो, केन्द्रीय सरकार की सम्मति में नितक भ्रष्टाचार समझा जाता है, अथवा
 - (3) यदि वह बोर्ड के अध्यक्ष से अनुपस्थिति की स्वीकृति लिये बिना बोर्ड की तीन लगातार बठकों से अनु-पस्थित रहता है, अथवा
 - (4) यदि केन्द्रीय सरकार की सम्मति में उसे बोर्ड का सदस्य बनाय रखना अवांछनीय सम**ा जाता है**।
- (भ) बोडों के सचिव, केन्द्रीय बोर्ड के अध्यक्ष की सहमित से अन्य बोडों के एक या अधिक गैर-सरकारी सदस्यों तथा ऐसे सदस्यों या व्यक्तियों को, जो खण्ड (उ) के अन्तर्गत बताये गये याता भत्तों इत्यादि के अधिकारी होंगे, किसी भी बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिये आमंत्रित कर सकते हैं।
- (अ) बोर्ड की बठक उसके अध्यक्ष द्वारा निश्चित स्थान और समय पर होगी।
- (ट) भारत में विद्यमान प्रत्येक सदस्य को हर एक साधारण बैठक के लिये निश्चित समय और स्थान का नोटिस इस प्रकार की बैठक से कम से कम 15 दिन पूर्व दिया जायेगा तथा प्रत्येक सदस्य को उस बैठक में निपटाई जाने वाली एक कार्य सूची भी दी जाएगी।

बगर्ते कि अध्यक्ष द्वारा जब कोई आपातिक बैठक बलाई जाती है तो इस प्रकार का नोटिस देना आवश्यक नहीं होगा।

- (ठ) कोई भी कार्य, जो सूची में न हो, संबंधित बोर्ड के अध्यक्ष की अनुमति बिना बैठक में उस पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (अ) अध्यक्ष बोर्ड की उन बैठकों की अध्यक्षता करेगा जिनमें वह उपस्थित हो। यदि अध्यक्ष किसी बैठक में अनुपस्थित हो तो उपस्थित सदस्य बठक की अध्यक्षता करने के लिये किसी एक सदस्य का चुनाव कर लेंगे और इस प्रकार निर्वाचित सदस्य उस बैठक में अध्यक्ष की सम्पूर्ण शक्तियों को काम में लायेगा।
- (द) बोर्ड की किसी बैठक के प्रत्येक प्रश्न का निर्णय उपस्थित सदस्यों तथा उस प्रश्न पर मतदान के बहुमत से किया जायेगा। मतों के समान विभाजन के मामले में अध्यक्ष अतिरिक्त मत देगा।

(ण) बोर्ड की हर एक बैठक की कार्यवाही भारत में विद्यमान सभी सदस्यों में परिचालित की जायेगी और इसके पश्चात् इसे कार्य-विवरण पुस्तक में दर्ज कर लिया जायेगा जिसे स्थायी रिकार्ड के लिये रखा जायेगा।

प्रत्येक बैठक की कार्यवाही के रिकार्ड पर बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

(त) किसी एक प्रदेश में व्यय के प्रस्तावों पर, जो नमक उप-कर से होने वाली आय में से किये जायेंगे, सर्वप्रथम प्रादेशिक बोर्ड द्वारा विचार किया जायेगा। इस प्रयोजन के लिये प्रारम्भिक अनु-मान जिनमें प्रस्ताव का ब्योरा और उसकी अनुमानित लागत एवं अन्य आवश्यक आंकड़े प्रादेशिक अधिकारियों द्वारा तैयार किये जायेंगे। प्रस्तावों सहित प्रादेशिक बोर्डी की सिफारिशों पर तत्पश्चात् केन्द्रीय बोर्ड द्वारा विचार किया जायेगा।

विकासोन्मुख एवं श्रम कल्याण संबंधी निर्माण कार्यों, जिनमें से प्रत्येक पर 40,000 रु० तक लागत आती हो, को कार्यान्वित करने के लिये केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड को उसकी अन्तिम सिफारिशें प्राप्त करने के लिये उल्लेख किये बिना स्वयं प्रादेशिक बोर्डों द्वारा स्वीकृति दी जा सकती है।

- (थ) केन्द्रीय बोर्ड की सिफारिशें स्वीकृति के लिये केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की जायेंगी जिसके पश्चात् विस्तृत अनुमान तैयार किये जायेंगे। अनुमानों की मंजूरी सक्षम प्राधिकार द्वारा दी जायेंगी।
- (द) केन्द्रीय बोर्ड अथवा किसी भी प्रादेशिक बोर्ड के किसी भी कार्य अथवा कार्यधाही को केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि केन्द्रीय बोर्ड या किसी भी प्रादेशिक बोर्ड में, जैसी भी दशा हो, कोई स्थान रिक्त था या उसके संविधान में कोई दोष था।

आचेता

आदेश दिया गया कि इस संकल्प को सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, योजना आयोग, केबिनेट सचि-वालय तथा प्रधान मंत्री का सचिवालय को भेजा जाये। यह भी आदेश दिया गया कि यह संकल्प भारत के राजपत्न भाग 1, अपड 1 में प्रकाशित कराया जाये।

डी० एन० कृष्णमृति, अवर सचिव

पूर्ति तथा तकनीकी विकास विभाग

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 13 अक्तूबर 1965

सं० 19/1/65-क्रय 1—उद्योग और पूर्ति मंत्रालय (पूर्ति और तकनीकी विकास विभाग) में भारत सरकार ने 27 जुलाई, 1964 को संसद सदस्य श्री ए० एन० विद्यालंकार की अध्यक्षता में एक अध्ययन समिति नियुक्त की ताकि यह समिति पूर्ति और निपटान महानिदेशालय में संगठन, संरचना, कार्य-प्रणाली तथा क्रियाविधि का परीक्षण करे, विशेषकर, उन स्थलों का पता लगाए जहां कार्य में बिलम्ब होता है, जहां रूकावटें हैं और जहां प्रशासनिक असफलताएं सम्भव हो सकती हैं तथा उन के सुधार के लिए कार्यवाही का सुझाव दे ताकि भ्रष्टाचार के लिए अवसरों का निरसन हो सके।

- 2. अध्ययन समिति ने दिसम्बर, 1964 में उद्योग और पूर्ति मंत्रालय (पूर्ति और तकनीकी विकास विभाग) को अपनी अंतरिम रिपोर्ट पेश की।
- अध्ययन समिति की सिफारिणों तथा उन पर सरकार के निर्णय अनुबन्ध में दिए गये हैं।
- 4. अध्ययन समिति ने जो मूल्यवान कार्य किया है उसके लिये सरकार अपनी सराहना रिकाड पर लाना चाहती है।

आवेश

आदेश है कि संकल्प की एक प्रति सभी सम्बधित कार्यालयों / व्यक्तियों को भेज दी जाये।

यह भी आदेश है कि संकल्प भारत के राजपत्न में सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाये।

ना० रा० बनसोड, संयुक्त सचिव

अनुबन्ध

ऋम ख्या	अध्ययन समिति की सिफारिशें	सरकार के निर्णय	
1	2	3	
	अध्याय 3संगठन-ऋथ अमुभाग 1		
1.	सहायक पूर्ति निदेशक तथा अनुभाग अधिकारी के अधीन कमणः आयोजना तथा टेन्ड्र सैल और ठेका सैल खोलने का जो परीक्षण किया गया है तथा जिससे . टेन्ड्र पूछताछ और ठेकों की निकासी का केन्द्रीकरण हुआ है, उसे जारी रखा जाय तथा आगे बढ़ाया जाये ।	स्वीकृत	
2.	प्रयोगात्मक आधार पर दो निदेशालयों में निम्नलिखित अतिरिक्त कार्यवाही की जाये :—		
	(क) एक क्रय-अनुभाग एक सहायक निदेशक अथवा अनुभाग अधिकारी के अधीन होना चाहिए ।	स्वीकृत	
	(ख) एक अनुभाग में 2 से 3 सहायक/उच्च श्रेणी लिपिक और 2 अवर श्रेणी लिपिक हों। अनुभाग के कार्यभारी अधिकारी को एक आणुलिपिक दे दिया जाए ।	स्वीकृत	
	 (ग) दर-चालू ठेकों की मदों के लिए पृथक अनुभागों का संगठन किया जाय तथा उन्हें अनुभाग अधिकारी के कार्यभार में रखा जाए । 	स्वीकृत	
	 (ध) अनुभाग, जो ऐसे माल को प्राप्त करने का व्यौहार करते हैं जो दर-चालू ठेकों पर नहीं है, सहायक निदेशक के कार्यभार में रखा जाए । 	स्वीकृत	

2

अध्याय 4--संगठन--संगठन तथा प्रणासी

3. संगठन तथा प्रणाली यूनिट को सुदृढ़ बनाया जाए और उसमें एक कार्य अध्ययन सिमिति भी होनी चाहिए । इसे एक पूर्ण-कालिक निदेशक के अधीन रखा जाय तथा वर्तमान अमले के अतिरिक्त प्रत्येक में दो अनुभाग अधिकारियों के साथ दो सहायक दिए जाएं । निदेशक, कार्यमानक, कार्य अन्तवंस्तु की स्पष्टता का रूप वक्र करेगा, कार्य अध्ययन तथा केस अध्ययन इस दृष्टिकोण से करेगा ताकि कियाविधि में सुधार किए जा सकें, अमले की जरुरतों का निर्धारण हो सके और किए गए काम की मात्रा तथा गुणावस्था का ज्ञान हो सके ।

यह सामान्य रूप से मान लिया गया है कि पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा केस अध्ययन के लिए उचित देख-भाल और निदेशन हेतु संगठन तथा प्रणाली यूनिट को उपयुक्त रूप से सुदृढ़ बनाया जाए और सतर्कता, संगठन तथा विधि और शिकायत अनुभागों में अमले के ढांचे पर अंतिम सुझाव मिल जाने के उपरान्त निदेशक की नियुक्ति के प्रश्न पर विचार किया जाए।

आयोग और विकास प्रभाग

- 4. आयोग निदेशालय को पुनरूजीवित किया जाए और इसका नाम आयोग और विकास प्रभाग रखा जाए । इसको कार्य की निम्नलिखित मदों की ओर ध्यान देना चाहिए।
 - (क) बड़े मांग कर्त्ताओं से प्राप्त सामान्यभोक्ता सामान के मांग-पत्नों की रसीद एवं एकत्रिकरण करने के लिए एक व्यापक कार्येकम बनाना।
 - (ख) आयोजित उत्पादनको इष्टतम क्षमता तक लाने के लिए कच्चे माल का अग्रिम प्रबन्ध करना तथा माप और विशिष्ट विवरण का युक्ति-करण करना ।
 - (ग) हर एक उत्पादन यूनिट के भार तथा क्षमता का परीक्षण करना और इस आधार पर, माल के समय पर, वितरण को मुनिश्चित करते हुए, आईर देने के लिए सुक्षाव देना ।
 - (घ) माल की मानक शब्दावली तैयार करना ।
 - (ङ) मानकीकरण से देसी उत्पादन को प्रोत्साहित करना तथा इष्टतम संख्या तक बढ़ाना और कमी वाले माल के लिए दीर्घावधि करारों को सुनिश्चित करना ।
 - (च) स्थानीय उत्पादन कर्शाओं की परिमितता को घ्यान में रखते हुए यह निर्धारित और निश्चित करना कि नियत विशिष्ट विवरणों में कहां तक छूट दी जाए ।
- इस प्रभाग में एक तकनीकी योग्यता प्राप्त अमले का उपयुक्त कर्नीमंडल होना चाहिए जो कि विदेशी मुद्रा के साधनों के बोझ को कम करने की दृष्टि से ऐसे आयात माल का यथा-क्रम अध्ययन करे जिसमें आयातित कच्चे माल की खपत होती है।
- केसों पर विचार करने के लिए एक स्थायी विकास कमेटी बनाई जाए जिसमें आयोग तथा विकास प्रभाग, तकनीकी विकास विभाग, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् तथा पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के निरीक्षण कक्ष का एक-एक प्रतिनिधि हो । इस प्रभाग का प्रतिनिधि संयोजक के रूप में काम करेगा ।
- यह प्रभाग नियत मदों पर उचित उत्पादन खर्च की जांच करने में सहायता करेगा
 ताकि उस पर निर्धारित सम्भावनीय संभरकों से बातचीत की जा सके।

पूर्ति और निपटान महानिदेशालय में आयोग निदेशालय को पुनरूजीवित करने का निश्चय सरकार पहले ही कर शुकी है । अध्ययन समिति अपनी अन्तिम रिपोर्ट में अमले के ठीक-ठीक ढांचे की सिफारिश करेगी ।

यथोपरि ।

यथोपरि ।

यथोपरि ।

अध्याय 5-- अधिकारी वर्ग और अमले का प्रशिक्षण

8. गत तीन वर्षों में नियुक्त होने वाले समस्त सहायकों, उच्च श्रेणी लिपिकों, अवर क्षेत्र अधिकारियों, अवर प्रगित अधिकारियों तथा तकनीकी सहायकों के लिए प्रशिक्षण कोर्स का संगठन किया जाए। यह प्रशिक्षण दो महीनों तक लगभग डेढ़ घंटा प्रति दिन चले। प्रशिक्षण (1) पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के संगठन और कार्य, (2) करारों के सामान्य नियम, (3) अध कियाविधि, (4) संभरण प्रगित, (5) परिनिश्चित दावों का भुगतान, (6) लेखा परीक्षा-आपत्ति, और (7) टिपिकल केसों पर विचार-विमर्श, विषयों पर दिया जाए।।

स्वीकृति । यह मान लिया गया था कि प्रशिक्षण के लिए एक पूर्णकालिक अनुभाग अधिकारी की जरूरत होगी और अनुभाग अधिकारी के एक अतिरिक्त पद का सूजन किया जाएगा। यह भी मान लिया गया कि अध्ययन समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने तथा जरूरत के अनुसार अमले के घटाय-बढ़ाव पर विचार करने के पश्चात, निवल फालसू अमला अध्यर्पण कर दिया जाएगा।

उन समस्त पूर्ति सहायक निदेशकों के लिए जो पहले ही काम कर रहे हैं, एक 9. महीने के लिए विचार-गोष्ठियों तथा परिसंवादों का आयोजन किया जाए। (इस विचार-विमर्शों में टिपिकल केस अध्ययन, परिवीक्षण की तकनीक, प्रबन्ध, कार्यायोजन तथा नियंत्रण और जन संपर्कविषयों पर चर्चा की जाए। विभिन्न अधिकारियों के अनुभव में आई समस्याओं पर भी चर्चा की जा सकती है)।

प्रशिक्षण अनुभाग एक सहायक की सहायता के साथ, एक अच्छे अनुभाग अधि-10. कारी के अधीन होना चाहिए । प्रशिक्षण प्रोग्राम को संगठन और प्रणाली निदेशक प्रशासित करे तथा पाठ्य-विवरण और अनुदेश-पत्नों को तैयार करवाए।

अध्याय 6--- ऋय--- फर्मों का रजिस्द्रेशन

फर्म की बैंक रिपोर्ट यदि अच्छी हैतो उसका रजिस्ट्रेशन इसलिए न रोका जाए 11. कि फर्म ने इन्कमटैक्स निकासी प्रमाण पत्र पेश नहीं किया । शपथपत्र के आधार पर कि फर्म ने प्रार्थना पत्न देने के समय गत वर्ष का निर्धारित इन्कम टैक्स अदाकर दिया है, फर्मकी अस्थायी रजिस्ट्रेशन कर दी जाए । फिरभी फर्म से यह अपेक्षा की जाए कि रजिस्टर होने के एक वर्ष के अन्दर वह अनिवार्य रूप से इन्कमटैक्स निकासी प्रमाणपत्न पेश करे नहीं तो उसकी रजिस्ट्रेशन रह कर दी जाएगी।

छोटे पैमाने की यूनिटों को रजिस्ट्रेशन के लिए अपने आवेदन पत्न, राज्य के 12. उद्योग निदेशकों द्वारा नहीं भेजने चाहिए बल्कि जिस राज्य में वह छोटे पैमाने की यूनिट रजिस्टर हुई है वहां के उद्योग निदेशक के पत्न की एक प्रमाणित प्रति के साथ आवेदन पक्ष सीधे भेजने चाहिएं।

छोटे पैमाने की यूनिटों की भांति बड़े पैमाने की यूनिटों को भी उन्हें रजिस्टर न 13. करने के कारण बता देने चाहिए इसको छोड़ कर कि यदि उनकी रजिस्ट्रेशन न करने के कारण गोपनीय हैं।

अतिरिक्त एक-सी मदों अथवा नई मदों के रजिस्ट्रेशन के लिए नई निरीक्षण 14. रिपोर्ट जरूरी नहीं होनी चाहिए परन्तु शर्त यह है कि पिछली निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर फर्म में नियत माल के उत्पादन करने की क्षमता होनी चाहिए । उप निदेशक (न कि अनुभाग अधिकारी) को इस बात का निर्णय करना चाहिए कि फर्म में उन मदों के उत्पादन की क्षमता है जिनके लिए रजिस्ट्रेशन मांगी जा रही है और जिनका उत्पादन उस साज-सामान द्वारा हो सकेगा जोकि फर्म की पहली रिजस्ट्रेशन के समय उनके पास मौजूद था अथवा एक नई निरीक्षण रिपोर्ट आवश्यक है।

वर्तमान अनुदेशों, जो छोटे पैमाने की युनिटों को इस योग्य बनाते हैं कि वह 15. अपने यहां परीक्षण सुविधाएं न होने के कारण अपने माल का परीक्षण किसी निकटवर्ती परीक्षणालय से करा सकें, को दूहराने की आवश्यकता है।

रजिस्ट्रेशन और माल के निरीक्षण के लिए अमलों को यथासम्भव अलग रखा 16. जाए ।

पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा जांच रखने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए प्रार्थनापत्न 17. प्यक रूप से डायरी किए जाएं और बाकी प्रार्थनापन्नों की स्थिति जानने के लिए डायरी को हर सप्ताह बन्द कर दिया जाए।

पूर्व सप्ताह में रजिस्टर की गई फर्मों के साप्ताहिक विवरण का संचार बन्द कर इस मामले पर और विचार किया जाएगा । 18. दिया जाए क्योंकि ट्रेड-लिस्टों का अनुरक्षण उचित रूप से नहीं हो रहा तथा महीनों से रिजस्टर हुई कई फर्मों को टेंडर नहीं भेजे जा रहे। संबंधित अनुभागों को उन मदों का जिनके लिए फर्म रजिस्टर की गई है, संकेत देने की बजाए, रजिस्ट्रेशन अनुभाग को एक ज्ञापन जारी करना चाहिए ताकि देडलिस्टों में संशोधन करने के लिए तत्कालिक कार्यवाही की जा सके । ऐसान करने पर जिम्मेदारी निश्चित की जाए।

पूर्ति और निपटान महानिवेशालय मानक शर्ती और प्रबन्धों की उन धाराओं में 19. संशोधन करेजो सामान्य व्यापार व्यवहार के अनुकूल नहीं हैं, आम तौर पर सम्भरकों को अस्वीकृत हैं और वस्तुतः व्यक्तिगत केसों में जिनका साधारणतया संशोधन होता है।

सिद्धान्त: स्वीकृत। यह भी मान लिया गया कि प्रशिक्षण का एक विभिन्न कोर्स, मानतयः संक्षिप्त नवीकरण पाठ्यक्रम, का आयोजन भी वर्तमान उप-निदेशकों के लिए किया जाए ।

स्वीकृत । प्रशिक्षण प्रोग्राम, पूर्ति और निपटान में संगठन और प्रणाली महानिदेशालय प्रभाग के अध्ययन द्वारा प्रशासित किया जाएगा ।

स्वीकृत ।

स्वीकृत ।

स्वीकृत । यह निर्णय करने से पूर्व कि नई क्षमता रिपोर्ट आवश्यक है या नहीं, निरीक्षण कक्ष से परामर्श करना होगा ।

स्वीकृत । इस सिलसिले में जरूरी अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

स्वीकृति । इस निर्णय को पूर्ति और निपटान महानिदेशालय एक दो परिमंडलों में प्रयोगात्मक रूप से कार्यान्वित करने का प्रयत्न करेगा ।

स्वीकृत ।

20. पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, वित्त और विधि मंत्रालयों के प्रतिनिधियों से बनी एक कमेटी इन शर्नों और प्रतिबन्धों का संवीक्षण करें और ट्रेड के प्रतिनिधियों से परामर्श करे।

यह निर्णय किया गया है कि पृथक् सब-कमेटी न बनाई जाए । अध्ययन समिति करारों की शतों और प्रतिबन्धों को, जहां तक यह खास पदार्थों पर लागू होते हैं, विस्तार-पूर्वक परीक्षण करे और जब कभी जरूरत हो, विधि-मंत्रालय, पूर्ति विभाग तथा विस मंत्रालय के अधिकारियों को परीक्षण में शामिल कर ले।

21. इसको छोड़कर कि जब केस ऊपर उब्धृत श्रेणी में आता है, जो फर्म स्वभावतः पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के मानक गर्ती और प्रतिबन्धों में परिवर्तन चाहती है, उसकी सरकारी रिजस्ट्रेगन हटा देनी चाहिए।

स्वीकृत ।

22. प्रगति-काङों के उचित ढंग से अनुरक्षण के लिए अनुभाग को चार अतिरिक्त लिपिकों से सुदृढ़ बनाया जाए।

यह निर्णय किया गया है कि अमला निरीक्षण
यूनिट की रिपोर्ट के प्रकाश में अध्ययन समिति
इस सिफारिश का पुनिवलोकन करे। अमला
निरीक्षण यनिट ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश
की थी कि अन्य मदों के साथ प्रगति काढों
के अनुरक्षण के लिए पूर्ति और निपटान
निदेशालय में लगाई गई अनुचालित सेम
मशीनों का उपयोग किया जाए।

23. प्रगति काडों में वह मालाएं दिखाई जाएं जिनको मूल्य में कभी के विचलम के अधीन स्वीकार किया गया है। उस फर्म को जिसका माल बहुधा विचलन के अधीन स्वीकृत किया जाता रहा है, पूर्ति और निपटान महानिदेशालय ठेके न दे क्योंकि वह कीमतों को घटा कर यथार्थ सम्भरकों का निरसन करने का कारण बनते हैं।

स्वीकृत ।

24. पूर्व वर्ष की प्रगति का पुर्निवलोकन करते हुए, जनवरी से मार्च महीनों में रिज-स्ट्रेशन उपनिदेशक द्वारा प्रगति कार्डी का वार्षिक पुर्निवलोकन होना चाहिए ।

स्वीकृत ।

अध्याय ७--- ऋय

1-सूती बस्ध

25. पूर्ति निदेशक (बस्त्र) बम्बई को निम्नलिखित बंधित अधिकार दिए जाएं :——
(क) चार लाख की कीमत के मांगपत्नों की मांगों के विज्ञापन के लिए पर्ण

(क) चार लाख की कीमत के मांगपत्नों की मांगों के विज्ञापन के लिए पूर्ण अधिकार।

(ख) उन करारों में जो उसके क्रय अधिकारों के अन्तर्गत नहीं आते, नेमी संशोधन करने के लिए पूर्ण अधिकार, उदाहरणार्थ :— बीस लाख से कम कीमत की मांगों की अधि-प्राप्ति को आयोजित करने के लिए उप-निदेशक (वस्त्र) बम्बई को अधिकार दिया जाए और चार लाख से ऊपर कीमत वाली मांगों के लिए स्थानीय वित्तीय प्राधिकारी की सहमति लेंनी चाहिए।

- (1) प्रेषित के पते में परिवर्तन
- . . . स्वीकृत ।
- (2) निरीक्षण अधिकारी का परिवर्तन

स्वीकृत ।

(3) प्रेषण अनुदेशों में परिवर्तन

यह निर्णय किया गया है कि पूर्ति निदेशक (वस्त्र)
को उपमहानिदेशक के अधिकार दे दिए जाएं
और जहां वित्तीय अड़चनें हों, वहां स्थानीय
वित्तीय अधिकारी के परामर्श से उन करारों
में संशोधन कर सके जिनमें ऐसा परामर्श सामान्यता जरूरी हो।

(4) स्वीकृत मालाओं के बारे में मूल्य में कमी के साथ विचलन के अधीन माल की स्वीकृति।

संबंद्ध निरीक्षणालय की सिफारिशों के आधार पर मूल्य में उपयुक्त कमी के साथ विचलन के अधीन स्वीकृत किए गए केसों को अंतिम रूप देने के हेतु पूर्ति निवेशक (वस्त्र) को विधत अधिकार पहले ही विए जा चुके हैं।

(5) जहां मांगकर्त्ता की सहमति हो और कीमतों का भुकाव अधोमुखी न हो, वहां वितरण अवधि को बढ़ाने की मंजूरी (सम्बद्ध वित्त प्राधिकारी के परामर्श से जारी हो) !

स्वीकृत ।

- (6) जिन करारों में ठेका देते समय उत्पादन शुल्क के चालू रेटों की व्यवस्था की गई हो और जहां माल का वितरण समय के अन्दर हो गया हो ऐसे केसों में उत्पादन शुल्क की दर की व्यथस्था के लिए पूर्ण अधिकार।
- तीस लाख रुपए की मालियत से कम करारों के विषद्ध निर्मित भाल से संबंद्ध उत्पादन शुल्क के लिए स्वीकृत।
- 25 में (1) से (5) तक के अधिकार दूसरे प्रादेशिक कार्यालयों और साथ ही 26. मुख्यालय के निदेशालयों को विए जाएं।
- मुख्यालय के निदेशकों तथा बम्बई और कलकत्ता के प्रादेशिक कार्यालयों तक स्वीकृत । कानपूर और मद्रास के प्रादेशिक कार्यालयों से संबंध कोई विसीय प्राधिकारी नहीं है अतः उन्हें वर्धित अधिकार न दिए जाएं।
- 27. सिलाई धागा, बटन, डस्टर तथा तौलिए जैसी पूनरामांग प्रकार की मदों के दर-चालू ठेके निश्चित किए जाएं। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के साथ किए गए करारों के कार्य-क्षेत्र को बजाए दिल्ली और नई दिल्ली तक सीमित रखने के समस्त देश के लिए बढ़ाया जाए।
- स्वीकृतः ।
- 28. प्रस्तावित आयोग और विकास प्रभाग, विभिन्न वस्त्र-मदों के लिए रक्षा-विशिष्ट विवरणों का पुनर्विलोकन करे और विशेष हालतों में इन में छुट दे।

सिद्धान्ततः स्वीकृत ।

2-- मदीन टल और अध्य इंजीनियरी एवं तकनीकी माल

- दुपर्ती टेन्डर संवीक्षण तथा स्वीकार्य आफर की सिफारिश के लिए मांगकर्त्ता को 29. स्वीकृत । साधारणतया नहीं भेजा जाना चाहिए ।
- जहां निश्चित कारणों की वजह से संदर्भ अनिवार्य हो तो वहां केवल उपमहा-30. निदेशक के अनुमोदन से ही दुपर्ती टेन्डर भेजे जार्ये।
- संगठन और प्रणाली यूनिट को यह बात, कैसे अध्ययन करते समय और उच्च स्वीकृत । 31. अधिकारियों को गोपनीय रिपोर्ट लिखते समय, ध्यान में रखनी पाहिए ।

3—उत्तर टेण्डर बात चीत—प्रतिमिवेद और टेण्डरों का रह करना

पूर्ति और निपटान महानिदशालय को उत्तर टेन्डर बातचीत और प्रतिनिवेद को सिद्धान्ततः स्थीकृत । 32. टालना चाहिए । यदि विशेष केसों में प्रतिनिवेद और बातचीत की नौबत आ ही जाए तो वह, मद की मूल्य-संरचना भली भांति जान लेने के पश्चात्, युक्तिकरण के आधार पर की जानी चाहिए।

- पिछले सम्भरक से (यदि टेन्डर के विरुद्ध उसने दाम नहीं बताए) उसके दाम न 33. बताने के कारण पूछने तथा दाम बताने के लिए आमन्त्रण करने की प्रणाली को पूर्ण रूप से रोक देना चाहिए ।
 - होगी, स्वीकृत ।
- उपमहानिदेशक के पूर्व अनुमोदन के साथ टेन्डरों को रद्द किया जाए। 34.

टेन्डरों को रद्द करने के उपयुक्त अनुदेश पूर्ति विभाग द्वारा पहले ही जारी कर दिए गए हैं ।

इसे छोड़कर कि पिछले संभरक से उसके वाम

न बताने के कारण पूछने पर कोई रोक नहीं

अध्याय 8— निरीक्षण

1---नीति पर पमावचार

- जिन फर्मों के पास पर्याप्त प्रकार-नियंत्रण तथा अत्यन्त योग्य तकनीकी अधि-35. कारी हैं, उनसे उपयुक्त गारेन्टी मिलने पर तथा निम्नलिखित सुरक्षणों के पालन करने पर, बिना निरीक्षण के माल संभरण करने दिया जाए :---
- भौतिक निरीक्षण के अभित्याग तथा विनिर्माता के समाश्वासन पर माल को स्वीकार करने के बारे में जरूरी अनुदेश, पूर्ति विभाग द्वारा अक्तूबर, 1964 में जारी किए जा चुके हैं।
- (क) सुरक्षा मदों में कोई रियायत नहीं वी जाएगी।
- (ख) जहां अनुज्ञा दी, फर्म से प्रकार-प्रमाणपत्र अनिवार्य होगा ।
- (ग) फर्म से पर्याप्त समाक्ष्वासन के लिए आग्रह करना चाहिए ।
- (घ) उप महानिदेशक (निरीक्षण), उप महानिदेशक (पूर्ति) और पूर्ति मंत्रालय के प्रतिनिधि, जो उप-सचिव की पदवी से नीचे न हो, की एक कमेटी को फार्मों का न्याय-युक्त चुनाव करना चाहिए।
- (इ.) सब से पहले, सारे मामले का एक वर्ष के लिए प्रयोगात्मक परीक्षण किया जाए । तदुपरान्त स्थिति का पुनर्विलोकन किया जाए ।

2--- সুত্র

जूट-माल के सम्भरकों की पिछली प्रगति के आधार पर, सप्लाई से पूर्व निरीक्षण सिद्धान्ततः स्वीकृत । 36. के प्रतिबन्ध का अभित्याग कर दिया जाए । फर्मों के चुनाव का काम, पूर्ति और निपटान महानिदेशक, पूर्ति और निपटान उप महानिदेशक और पूर्ति विभाग के प्रतिनिधि से बनी एक कमेटी पर छोड़ दिया जाए । इस प्रकार चुनी गई फर्म को भारतीय मानक संस्था की प्रमाणपत्न योजना के अधीन आने के लिए कहा जाए । फर्मों को अपने उस माल के लिए उपयुक्त गारेन्टी देनी चाहिए जिसको सरकार प्रारूपित करना चाहे।

अध्याम 9-निरीक्षण (विविध)

जरूरी माल के बारे में एक समान निरीक्षण कियाविधि तथा मानक को बनाने के 37. लिए कदम उठाने चाहिएं । यह काम एक उपयुक्त योग्य अधिकारी, जैसे निरीक्षण निदेशक, को सौंप देना चाहिए । यदि मानक बना दिए जाएं तो जब कभी काम में अधिकता आए, अतिरिक्त अमला दिया जा सकता है ताकि निरीक्षण काम में दर्जन हो।

सिद्धान्ततः स्वीकृत ।

स्वीकृत ।

- 38. एक केन्द्रीय स्थान पर प्राप्त होनेवाली समस्त प्रार्थनाओं को डायरी करने के तत्काली प्रबन्ध किए जाएं और यह बताया जाए कि उनका वितरण कैसे हुआ है । प्रार्थना के निपटान को भी डायरी में दर्ज किया जाए । निरीक्षण निदेशक को डायरी की प्रति सप्ताह जांच करनी चाहिए ताकि वह हरएक निरीक्षक के पास कार्यभार की स्थिति का पता लगा सके।
- निरीक्षकों की डायरियों में निरीक्षण के परिणामों का भी निर्देशन होना चाहिए, 39. स्वीकृत । जैसे निरीक्षित माल की गुणावस्था और माक्षाओं जो स्वीकृत अथवा रद्द कर दी गई और इन डायरियों की ग्रुप इंचार्ज द्वारा हर महीने की बजाए, जैसा आजकल किया जाता है, हर सप्ताह जांच होनी चाहिए । इसके अतिरिक्त, प्रत्येक निरीक्षक के पास बचे काम को ध्यान में रखते हुए और ग्रुप के कार्य-भारी अधिकारी के अनुमोदन से, हर एक निरीक्षक के लिए अग्रिम साप्ताहिक

प्रत्येक निरीक्षक के पास अने काम का विवरण निर्धारित फार्म में तैयार करना स्वीकृत । 40. चाहिए ।

41. निरीक्षण अमले को अधिक समय, कार्यालय के बजाए निरीक्षण में लगाना चाहिए । उन स्थानों में जहां फर्में, निरीक्षण कार्यालय से अधिक दूरी पर स्थित हैं, निरीक्षण के छोटे उप-केन्द्र खोले जाएं ताकि अपराह्न में तमाम निरीक्षण अधिकारियों को केन्द्रीय कार्यालय में जाने की जरूरत को दूर किया जा सके । केवल ग्रुप अधिकारी को प्रतिविन केन्द्रीय कार्यालय में जाना चाहिए तथा विभिन्न केसों पर आदेश लेने चाहिए । साधारण स्पष्टीकरण उप-केन्द्र से प्राप्त किया जाए ।

कार्यक्रम बनाना चाहिए।

यह सुझाव कि निरीक्षण अमला अधिक समय कार्यालय के बजाए निरीक्षण में लगाए सिद्धान्ततः स्वीकृत ।

- निरीक्षण अधिकारियों को काफी चलता फिरता रखना चाहिए और ऐसा करने के 42. लिए निम्नलिखित कार्य किए जाएं :---
 - (क) प्रत्येक निरीक्षण कार्यालय में अग्रदाय रखा जाए ताकि ट्रर पर जाने वाले निरीक्षण अधिकारी को अग्रदाय में से पेशगी दी जा सके ।

स्वीकृत । आरम्भ में अग्रदाम बम्बई, कलकला, मद्रास तथा नई विल्ली के निरीक्षण नि-देशालयों में रखा जाए। तत्पश्चात, निरीक्षण निदेशालयों में इसे प्रणाली की सिकयता का पुनर्विलोकन करके अन्य प्रादेशिक कार्यालयों में चाल किया जाएगा।

(ख) सरकारी कोटे से भिन्न प्रकार की गाड़ियां हासिल करने के लिए नि-रीक्षण अधिकारियों को प्राथमिकता दी जाए ।

मामला विचाराधीन है ।

(ग) जब कभी शीघ्रतया रेल में बुकिंग नहीं मिलती और इस कारण विसम्ब हो जाने की संभावना हो जाए तो निरीक्षण अधिकारियों के वायुयान से याता की आज्ञा दे देनी चाहिए । यह आज्ञा देने के लिए, सरकार निरीक्षण निवेशक को अधिकार दे।

अस्वीकृत ।

अध्यक्ष

शिक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 सितम्बर 1965

सं० 22(22)/62 एम० आर० II—भारत सरकार ने जीव-विज्ञान के लिए एक राष्ट्रीय समिति स्थापित करने का निर्णय किया है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

- प्रो० पी० माहेश्वरी, 'वनस्पति-विज्ञान-विभाग के प्रमुख', दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
- डा० के० सी० बोरा,
 जीव-प्रभाग,
 परमाणु शक्ति संस्थापन, ट्राम्बे,
 रिचार्डसन एण्ड कूडास बिल्डिंग,
 वाईकुल्ला, बम्बई ।
- 3. डा० ए० पी० गोपाला-अयंगर, निदेशक, बाइलाजी-प्रुप, परमाणु शक्ति संस्थापन, ट्राम्बे, रिचार्डसन एण्ड क्ष्डास बिल्डिंग, बाईक्ष्ला, बम्बई ।
- डा० बी० पी० पाल,
 महानिदेशक,
 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्,
 नयी दिल्ली ।
- डा० एन० के० पणिक्कर,
 निदेशक,
 भारतीय सागर अभियान,
 वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंघान परिषद,
 नई दिल्ली ।
- डा० ए० एस० पेन्टल,
 निदेशक,
 घरलभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट,
 दिल्ली ।
- 7 डा० बी० आर० शेषाचर, प्राणि-विज्ञान विभाग के प्रमुख, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ।
- रेवेरण्ड एच० सन्तापी, निदेशक, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण, कलकत्ता ।
- डा० ओ० सहीकी,
 टाटा इंस्टीट्यूट आफ फण्डामेन्टल,
 रिसर्च, कोलाबा,
 बम्बई।

राष्ट्रीय समिति का कार्य अन्तर्राष्ट्रीय जीव-विज्ञान संघ के लक्ष्यों का ध्यान रखते हुए विशेषतः उनकी अन्तर्राष्ट्रीय आवश्यकः ताओं के सम्बन्ध में जीव-विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन का देश में उन्नत बनाना तथा समन्वय करना होगा, अर्थात् :---

- (क) जीव-विज्ञान के अध्ययन को बढ़ाधा देना,
- (ख) अनुसंधान तथा दूसरी वैज्ञानिक गतिविधियों को (जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है) शुरु करना, सुविधाएं देना तथा समन्वय करना,
- (ग) सहकारी अनुसंधान के परिणामों के विचार विमर्श तथा प्रसार को सुनिश्चित करना,
- (घ) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के संगठन को उन्नत बनाना तथा उनकी रिपोर्ट के प्रकाशन को मदद देना।

एम० एम० मल्होला, उप-सचिब

नई दिल्ली, दिनांक 1 अक्तूबर 1965

संकस्य

सं० एफ० 1-2/65-पी० ई० 2—इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या ए० एफ० 1-2/65-पी० ई० 2 दिनांक 12 जुलाई, 1965 के कम में, शिक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 11 -16/58-पी० ई० 2 दिनांक 2 मार्च 1959 के अन्तर्गत प्रकाशित तथा समय-समय पर संशोधित, अखिल भारतीय खेल परिषद की स्थापना से संबन्धित संकरूप में, निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:—

उपर्युक्त संकल्प की धारा 3 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित लिख दिया जाय:----

"3(1) परिषद में मारत सरकार द्वारा नामजद 19 सदस्य होंगे, जिनमें से एक सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेगा। नामजद मदस्यों में से कम से कम एक महिला होगी। इसके अतिरिक्त, खेल के क्षेत्र में विख्यात दो व्यक्तियों को परिषद सहयोजित कर सकेगी। नामजद अथवा सहयोजित व्यक्ति, राज्य खेल परिषदों को छोड़कर किसी अन्य खेल संस्था का पद धारण नहीं करेंगे।"

आवेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दी जाय और सभी संबंधित व्यक्तियों/ संगठनों को भेज दी जाय।

भ्०प्र० बागची, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 22 अक्तूबर 1965

सं० एफ० 1-2/65-पी० ई० 2—इस मंत्रालय की 14 जुलाई, 1965 की अधिसूचना सं० एफ० 1-2/65-पी० ई० 2 के कम में, अखिल भारतीय खेल परिषद ने निम्नलिखित व्यक्तियों को, इसी समय से, और 15 जुलाई 1967 तक अपने सदस्य के रूप में सहयोजित किया है:—

- ले० जनरल एम० एस० वाडालिया,
 कुतुब स्टड एण्ड एग्रीकल्चरल फार्म,
 गादिआपुर, पो० महरौली, नई दिल्ली-30, और
- श्री पी० एल० मेहता,
 18, कौटिल्य मार्ग, डिप्लोमेटिक एनक्लेव,
 नई दिल्ली-11।

रोशन लाल आनंद, अवर सचिव

भम और रोजगार मंत्राह्मय

नई दिल्ली, दिनांक 22 अन्तूबर 1965

मं० ई० एण्ड पी०-4/1/30/64— चूंकि 20 विसम्बर, 1958/29 अग्रहायन, 1880 के भारत के राजपत्र के भाग 1 खण्ड 1 में प्रकाशित श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या-ई० एण्ड पी०-4(24)/58, तारीख 12 दिसम्बर, 1958 में अधिसूचित केन्द्रीय मजदूर शिक्षा बोर्ड में भारत सरकार के प्रतिनिधियों के गठन में कुछ और परिवर्तन किया गया है, इस लिए जनता की सूचना के लिए एतद् द्वारा मूचित किया जाता है कि उक्त सोसायटी के नियमों और विनियमों के नियम 3 (बी) के अनुसार भारत सरकार एतद् द्वारा श्री एफ० एच० बस्लीभाय, संयुक्त सचिय (प्रणासन), बिस मंत्रालय, व्यय विभाग, को इस अधिसूचना की तारीख से श्री पी० सद्गोपन, आन्तरिक विस्त सलाहकार और पदेन उप सचिव के स्थान पर केन्द्रीय मजदूर शिक्षा बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है।

2. तदनुसार उक्त अधिसुचिना में अधिसुचित भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति सम्बन्धी प्रविष्टि में

> "3. श्री पी ० सद्गोपन, भारत सरकार के आन्तरिक वित्त सलाहाकार प्रतिनिधि' और पदेन उप सचिव

के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाय:---

"3. श्रो एफ० एच० बल्लीभाय, संयुक्त सिचव (प्रशासन), भारत सरकार के व्यम विभाग, वित्त मंत्रालय, प्रतिनिधि " नई दिल्ली।

ओ० पी० तलवाड़, अवर सचिव

संच्यप

नई दिल्ली, दिनांक 27 अक्तूबर 1965

सं० डब्स्यू० बी०-2(19)/65/1--श्रम और रोजगार मंत्रालय के संकल्प संख्या डब्ल्यू० बी०-2(1)/62(1), तारीख 3 मई 1963 में तरमीम करते हुए श्री एन० के० दास को श्री आर० एम० होनावर के स्थान पर, जिन्होंने त्याग-पत्न दे दिया है,

कच्चे लोहे के खनन उद्योग के केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड, कलकत्ता में स्वनन्त्र सदस्य नियन्त किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाएं।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्न में प्रकाशित किया जाए।

सं० डब्ल्यू० बी०-2(19)/65/2--श्रम और रोजगार मंत्रालय के संकल्प संख्या ढब्ल्यू० बी०-2(1)/62(2), दिनांक 3 मई 1963 में तरमीम करते हुए श्री एन० के० दास को श्री आर० एम० होनावर के स्थान पर, जिन्होंने त्यागपत वे दिया है, चुना और डोलोमाइट खनन उद्योगों के केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड, कलकत्ता में स्वतन्त्र सदस्य नियुक्त किया जाता है।

आपेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाएं।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

हंस राज छाबड़ा, अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 14th August 1965

No. 88-Pres./65.—The President is pleased to award the President's Police and Fire Services Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Gujarat Police:—

Name of the officer and rank

Shri Bhausaheb Shivajirao Shirke, Assistant Commandant (Officiating). State Reserve Police Force, Gujarat.

Statement of services for which the decoration has been

At the time of the massive Pakistani attack on the Indo-Pakistan border in the Rann of Kutch, in April 1965, Shri Bhausaheb Shivajirao Shirke was commanding a State Reserve Police Garrison at Chhad Bet. When the Police Post at Sardar was attacked, the enemy concentrated a large force opposite Chhad Bet. Undaunted by this intimidation and the presence of numerically superior forces with heavy armour, Shri Shirke carried out successive patrols along the border till the standing post at Hanuman Talai was shelled on the 21st April 1965. On the 23rd April, the police post at Winghi was subjected to heavy firing and on the 24th April, the enemy artillery started shelling Chhad Bet post and firing with MMGs and 3" mortars. The Pakistani forces advanced up to 1200 yards from the perimeter of the Chhad Bet Post, but the Police force, under the able leadership of Shri Shirke, vigorously engaged the enemy forces and repulsed their concentrated attack after a grim fight which lasted for 3 hours.

In this encounter, Shri Bhausaheb Shivaijrao Shirke, exhibited conspicuous gallantry, exemplary courage, leadership and devotion to duty of a high order.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police and Fire Services Medal.

No. 89-Pres./65.—The President is pleased at award the President's Police and Fire Services Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Gujarat Police:—

Name of the officer and rank

Shri Bhaskar Anandarao Deokar, Head Constable, State Reserve Police Force, Group-II,

Gujarat.

Statement of services for which the decoration has been

On the 21st April 1965, the Pakistani armed forces heavily shelled the standing patrol post of the Chhad Bet garrison at Hanuman Talai. As a result of the heavy enemy fire, one Head Constable of the standing patrol post was found to be missing. The Post Commander deputed Head Constable Bhaskar Anandarao Deokar to search for the missing Head Constable. Despite firing from the enemy, Head Constable Deokar set out and succeeded in finding the body of the missing Head Constable and managed to bring it, along with ammunition and equipment, back to Chhad Bet Post. On the 23rd and 24th April, when the enemy artillery

started shelling Chhad Bet Post and firing with MMGs and 3" mortar, Head Constable Deokar moved from place to place inside the post and organised the removal of essential arms and ammunition to a safe place at grave risk to his

Head Constable Bhaskar Anandarao Deokar displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order in utter disregard for his personal safety.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police and Fire Services Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 24th April 1965.

No. 90-Pres./65.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Gujarat Police:—

Name of the officer and rank Shri Balram Ramchandra Malsuro State Reserve Police Force, Group-II. Guiarat.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

Constable Balram Ramchandra Malsure was with the detachment of the Stafe Reserve Police Force stationed at Chhad Bet when Pakistani armed forces attacked the Police Post on the 23rd and 24th April 1965. On the 24th April, when after heavy and continuous artillery and mortar fire it became impossible for the small police party to withstand the massive and concentraed attack by the numerically superior enemy forces, the Post Commander ordered the removal of records and surplus arms and ammunition from the Post to a safer position. In this very difficult and dangerous task in the face of such heavy fire, Constable Balram Ramchandra Malsure was of immense help. Defying the shelling and in complete disregard of his own safety, Constable Malsure moved from place to place, collected valuable records, surplus arms and equipment and loaded them in vehicles, to be removed to a safer place. Throughout this time, Constable Balram Ramchandra Malsure displayed outstanding courage and devotion to duty of a high order. standing courage and devotion to duty of a high order.

2. This award is made for callantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 24th April 1965.

No. 91-Pres./65.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Gujarat Police:—

Name of the officer and rank

Shri Mangalsingh Ishawarsingh Darwal, Head Constable (Officiating), State Special Reserve Police,

awarded.

Statement of services for which decoration has been

Head Constable Mangalsingh Ishawarsingh Darwal was with the State Reserve Police Force detachment stationed at Chhad Bet when the Pakistani armed forces attacked the

Police Posts in April 1965. When the enemy crossed the international border at Kanjarkot prior to attacking Sardar Post, Head Constable Darwal displayed great keenness and initiative in carrying out patrols and reconnaissances, driving his vehicle close to the border at considerable personal risk. He continued his mobile patrols right up to the border in spite of the threats from Pakistan Rangers. On the 22nd April, Head Constable Darwal retrieved the body of a Head Constable from the Hanuman Talai area in the midst of firing. Again on the 23rd and 24th April 1965, when Chhad Bet was heavily shelled, Head Constable Darwal carried out the removal of essential documents, arms and equipment to safer places and brought food for the personnel of the post in the midst of heavy shelling from the enemy. Head Constable Mangalsingh Ishwarsingh Darwal exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order in utter disregard for his personal safety.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 24th April 1965.

Y. D. GUNDEVIA, Secy. to the President.

PLANNING COMMISSION

RESOLUTION

National Advisory Committee on Public Cooperation New Delhi, the 26th October 1965

No. 6(1)/65-Pub.—The National Advisory Committee on Public Cooperation was constituted by the Government of India in 1958 for (i) reviewing and assessing the progress of Public Cooperation in relation to National Development, (ii) advising the Planning Commission from time to time regarding the progress of Public Cooperation in relation to the fulfilment of the Plan, and (iii) making suggestions and recommendations on matters of policy and on programmes relating to Public Cooperation.

- 2. In order to make this Committee more representative and broad-based, the Government of India have decided to reconstitute it as follows:
 - (a) Members of the Planning Commission
 - (b) Shri Amarnath Vidyalankar, M.P. Shri M. S. Gurupadaswamy, M.P. Shri Jaipal Singh, M.P. Shri C. R. Basappa, M.P. Smt. Renu Chakravarty, M.P. Shri Nath Pai, M.P. Prof. B. N. Prasad, M.P. Smt. Durgabai Deshmukh. Prof. N. R. Malkani, General K. M. Cariappa, Shri T. S. Bharde. Shri B. V. Baliga. Shri Ishwarbhai J. Patel.
 - (c) One representative each of the following organisations:—

All India Federation of Education.

All India Women's Conference.

All India Panchayat Parishad.

All India Women's Central Food Council.

All India Ex-servicemen's Federation.

All India Prohibition Council.

All India Boy Scouts Association,

Association for Moral & Social Hygiene in India.

Association of Schools of Social Work in India.

Association of Voluntary Agencies for Rural Development.

Bharat Sevak Samaj,

Bharat Krishak Samaj.

Bhartiya Adimiati Sevak Sangh.

Bharat Sadhu Samaj.

Bharat Scouts and Guides.

Bharatiya Grameen Mahila Sangh.

Balkan-Ji-Bari,

Central Social Welfare Board,

Catholic Charities, India.

Council for Social Development,

Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha.

Family Planning Association of India.

Gandhi Smarak Nidhl.

Harijan Sevak Sangh.

Indian Red Cross Society.

Indian Council for Child Welfare,

Indian Council of World Affairs.

Indian Cooperative Union.

Indian Conference of Social Work.

Kasturba Gandhi National Memorial Trust.

National Association of Teacher Educators.

National Cadet Corps and Auxiliary Cadet Corps.

National Council of Y.M.C.A.

National Parent Teacher Association of India.

National Cooperative Union of India.

National Consumer Service.

National Council of Women in India,

National Productivity Council.

Rashtrabhasha Prachar Samiti.

Ramakrishna Mission.

Servant of Peoples Society.

Sanyukta Sadachar Samiti.

T.B. Association of India.

The Indian Medical Association.

Voluntary Blood Transfusion Service.

Young Women's Christian Association of India.

- 3. The Chairman of the Planning Commission will be the Chairman of the Committee. Shri Krishna Prasad will continue to function as Honorary Secretary.
- 4. The Committee may also coopt from time to time members for any specific item of work in which their association is required.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India.

K. A. P. STEVENSON, Jt. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-11, the 28th October 1965 CORRIGENDUM

No. 11/11/65-Ests(B).—In this Ministry's Resolution No. 11/11/65-Ests(B), dated the 9th September 1965, published in the Gazette of India dated 25th September 1965, the following words occurring in para 1 thereof may be omitted:—

"as a result of (constitutional changes) in those countries."

N. RAGHUNATHAN, Under Secy.

RULES

New Delhi-11, the 6th November 1965

No. 8/30/65-CS-II.—The rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in May 1966. for the purpose of filling temporary vacancies in the following Services/posts are published for general information:

- (i) Central Secretariat Stenographers' Service—Grade II;
- (ii) Railway Board Secretariat Stenographers' Service—Grade II;
- (iii) Indian Foreign Service (B)—(Grade II of the Stenographers' Sub-Cadre); and
- (iv) Posts of Stenographer in certain Departments and Offices of the Government of India not participating in the Central Secretariat Stenographers' Service/ I.F.S. (B)/Railway Board Secretariat Stenographers' Service. and such post in the Office of the Election Commission.
- 2. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix I to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

of the design of the community of the community

- 3. (1) A candidate must be either:-
 - (a) a citizen of India or,
 - (b) a subject of Sikkim, or
 - (c) a subject of Nepal, or
 - (d) a subject of Bhutan, or
 - (e) a Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or
 - (f) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan with the intention of permanently settling in India;

Provided that a candidate belonging to categories (c), (d), (e) or (f) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been granted by the Government of India, and if he belongs to category (f) the certificate of eligibility, will be valid only for a period of one year from the date of his appointment beyond which such a candidate will be retained in service subject to his having acquired Indian citizenship;

Provided further that Certificate of eligibility will not be necessary in the case of a candidate—

- (i) who had migrated to India from Pakistan before the nineteenth day of July 1948, and have ordinarily been residing in India since then.
- (ii) who had migrated to India from Pakistan on or after the nincteenth day of July, 1948, and have got themselves registered as citizens of India under Article 6 of the Constitution.
- Affects 6 of the Constitution.

 (iii) who falls within category (f) above and who is not a civizen of India and had entered service under the Government of India before the commencement of the Constitution, viz., 26th January 1950, and had continued in such service since then without a break. Any such person who re-entered or may re-enter such service after any break of such service after the 26th January 1950, will, however, require certificate of eligibility in the usual way.

Provided further that candidates belonging to categories (c), (d) and (e) above will not be eligible for appointment to the Indian Foreign Service (B)—(Grade II of the Stenographers' Sub-Cadre).

- (2) A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination and he may also provisionally be appointed subject to the necessary certificate being granted in his favour by the Government.
- 4. A candidate who does not belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or is not a resident of the Union Territory of Pondicherry or is not a resident of the Union Territory of Islands, or is not a repatriate from Ceylon, or is not a resident of the Union Territory of Goa. Daman and Din, or is not a migrant from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), shall not be permitted to compete more than twice at the examination, but this restriction shall be effective from the examination held in 1962.

Note 1.—For the purpose of this rule, a candidate shall be deemed to have competed at the examination once for all the Services/posts covered by the examination, if he competes for any one or more of the Services/posts.

Note 2.—A candidate shall be deemed to have competed at the examination if he actually appears in any one or more subjects.

- 5. (A) A candidate for admission to this examination must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of 24 years on 1st January 1966, i.e. he must have been born not earlier than 2nd January, 1942 and not later than 1st January, 1948.
- (B) The upper age limit will be relaxable up to the age of 35 years in respect of persons who are employed as Stenographers (including language Stenographers)/Clerks in the various Departments/Offices of the Government of India and have rendered not less than 3 years continuous service as Stenographer (including language Stenographer)/Clerk on the 1st Ianuary 1966, and continue to be employed either as Stenographer (including language Stenographer) or as Clerk under the said Government.

Provided that the above age relaxation will not be available to persons appointed as Stenographers, on the basis of earlier examinations, held by the Union Public Service Commission, in:—

- (i) Central Secretariat Stenographers' Service; or
- (ii) Railway Board Secretariat Stenographers' Service; or
- (iii) Indian Foreign Service (B); or
- (iv) The Intelligence Bureau.

Note—Service rendered by R.M.S. Sorters employed in Subordinate offices of P.&T Deptt, shall be treated as service rendered in the grade of Clerk for purpose of Rules 5(B) above

- (C) The upper age limit in all the above cases, will be further relaxable:—
 - (1) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;
 - (ii) up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after January 1, 1964;
 - (iii) up to a maximum of eight years if a candidate helongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a hona fide displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after January 1, 1964;
 - (iv) up to a maximum of five years if a candidate is a resident of the Union Territory of Pondicherry, and has received education through the medium of French, at one stage or another;

- (v) up to a maximum of four years if a candidate is a resident of the Andaman and Nicobar Islands;
- (vi) up to a maximum of three years if a candidate is an Indian citizen and is a repatriate from Ceylon;
- (vii) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu, and
- (viii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar),

SAVE AS PROVIDED ABOVE, THE AGE LIMITS PRESCRIBED ABOVE SHALL IN NO CASE BE RELAXED.

- N.B.—(i) The candidature of a person who is admitted to the examination under the age concession mentioned in Rule 5(B), above, is liable to be cancelled, if after submitting his application, he resigns from service or his services are terminated by his department, either before or after taking the examination. He will, however, continue to be eligible if he is retrenched from the service or post after submitting his application.
- (ii) A Stenographer (including language Stenographer)/Clerk who is on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.
- 6. Candidates who are employed in or under the Intelligence Burcau will be admitted, if otherwise eligible, to compete for vacancies in the Intelligence Burcau only. Other candidates, whether in Government service or not, if otherwise eligible, will be admitted to compete for vacancies in all the Services/Offices recruitment to which is made on the results of this examination.
- 7. Candidates must have passed one of the following examinations or must possess one of the following certificates:—
 - (a) Mutriculation examination of any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or an examination recognised by such a University as equivalent to its Matriculation examination;
 - (b) an examination held by a State Education Board at the end of the Secondary School Course for the award of a School Leaving, Secondary School, High School or any other Certificate which is accepted by the Government of that State as equivalent to Matriculation certificate for entry into Services;
 - (c) Cambridge School Certificate Examination; (Senior Cambridge);
 - (d) European High School Examination held by the State Governments;
 - (e) Tenth Class Certificate from the Technical Higher Secondary School of the Delhi Polytechnic;
 - (f) Tenth Class Certificate from a recognised Higher Secondary School or from a recognised school preparing students for the Indian School Certificate Examination:
 - (g) Junior Examination of the Jamia Milia Islamia. Delhi in the case of hona fide resident students of the Jamia only;
 - (h) Bengal (Science) School Certificate:
 - (i) Final School Standard Examination of the National Council of Education, Jadavpur, West Bengal (Since inception);
 - (j) The following French Examinations of Pondicherry;
 - (i) 'Brevet Elementaire', (ii) 'Brevet d' Enseignment Primaire de Langue Indienne'. (iii) 'Brevet D'etudes du Premier Cycle', (iv) 'Brevet D' Enseignement Primaire Superieur de I angue Indienne', and (v) 'Brevet de Langue Indienne' (Vernacular).
 - (k) Indian Army Special Certificate of Education;
 - (1) Higher Educational Test of the Indian Navy;
 - (m) Advanced Class (Indian Navy) Examination;
 - (n) Ceylon Senior School Certificate Examination;
 - (o) Certificate granted by the East Bengal Secondary Education Board. Dacca;
 - (p) School Leaving Certificate Examination of the Government of Nepal;
 - (q) Anglo-Vernacular School Leaving Certificate (Burma);
 - (r) Burma High School Final Examination Certificate;
 - (s) Anglo-Vernacular High School Fxamination of the Education Department, Burma (Pre-war);
 - (t) Post-War School Leaving Certificate of Burma;
 - (u) the 'Vinit' Examination of the Gujarat Vidyapith, Ahmedabad.
 - (v) Pass in the 5th Year of 'Lyceum' a Portuguese qualification in Goa, Daman and Diu.

- Note.—(1) In exceptional cases the Union Public Service Commission may treat a candidate, who has not any of the foregoing qualifications, as a qualified candidate, provided that he has passed examinations conducted by other institutions, the standard of which in the opinion of the Commission justifies his admission to the examination.
- (2) candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him eligible to appear at this examination but has not been informed of the result may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply provided the qualifying examination is completed before the commencement of this examination. Such a candidate will be admitted to the examination if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if he does not produce proof of having passed the examination, as soon as possible, and in any case not later than two months after the commencement of this examination.
- 8. (a) No male candidate who has more than one wife living or who having a spouse living marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life time of such spouse, shall be eligible for appointment to any of the Services/posts, appointments to which are made on the results of this competitive examination unless the Government of India after being satisfied that there are special grounds for doing so exempt any male candidate from the operation of this rule.
- (b) No female candidate whose marriage is void by reason of the husband having a wife living at the time of such marriage or who has married a person who has a wife, living at the time of such marriage shall be eligible for appointment to any of the Services/posts appointments to which are made on the results of this competitive examination unless the Government of India after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any female candidate from the operation of this rule.
- (c) A person married to a foreign national shall not be eligible for appointment to the Indian Foreign Service (B).
- 9. A candidate already in Government service whether in a permanent or a temporary capacity must obtain prior permission of the Head of the Department to appear for the Examination.
- 10. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the Service/post. A candidate, who after such medical examination, as may be prescribed by the competent authority, is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medically examined.
- 11. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.
- 12. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.
- 13. Candidates must pay the fee prescribed in Annexure I to the Commission's Notice. No claim for a refund of the fee will be entertained except to the extent stated in that Annexure, nor can the fee be held in reserve for any other examination or selection.
- 14. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission,
- 15. A candidate who is or has been declared by the Commission guilty of impersonation or of submitting fabricated documents or documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false or of suppressing material information or otherwise resorting in any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination, or of using or attempting to use unfair means in the examination hall or of misbehaviour in the examination hall, may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution,—
 - (a) be debarred permanently or for a specified period:—
 - (i) by the Commission, from admission to any examination or appearance at any interview held by the Commission for selection of candidates; and
 - (ii) by the Central Government from employment under them;
 - (b) be liable to disciplinary action under the appropriate rules, if he is already in service under Government.
- 16. Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government of India.

Scheduled Castes/Tribes means any of the Castes/Tribes mentioned in the Scheduled Castes/Tribes Lists (Modification) Order, 1956, read with Scheduled Castes and Scheduled

- Tribes Orders (Amendment) Act, 1956, the Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956. The Constitution (Andaman & Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, and the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964.
- 17. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in the order of metit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate; and in that order so many candidates as are found by the Commission in their discretion to be qualified by the examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination.

Provided that any candidate belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes who though not qualified by the standard prescribed by the Commission for any Service/post, is declared by them to be suitable for appointment thereto with due regard to the maintenance of efficiency of administration, shall be recommended for appointment to vacancies reserved for members of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be.

Note 1.—Due consideration will be given to the preferences expressed by a candidate at the time of his application (c.f. Col. 28 of the application form), but a candidate may be assigned to any Service/post for which the examination is held.

N.B.—A reserve list containing names in the order of merit, the number of which would be determined by Government before the declaration of the results of the next examination, may be drawn up for eventual absorption in Grade II of the C.S.S.S. before the declaration of the results of the next Stenographers' Examination. Candidates indicating C.S.S.S. as one of their preferences should state clearly in their applications whether they would wish to be considered for inclusion in such a reserve list.

Note 2.—The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion, and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

- 18. Success in the examination confers no right, to appointment, unless Government are satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service/post.
- 19. Conditions of service relating to the Services/posts to which recruitment is being made through this examination, are briefly stated in Appendix II.

K. THYAGARAJAN, Under Secy.

APPENDIX I

1. The subjects of the examination, the time allowed and the maximum marks for each subject will be as follows:—

PART A-WRITTEN TEST

,	_	Subject	Time Allowed	Maximum Mark
	(i)	English	3 hours	100
(ii)	General Knowledge	3 hours	100

PART B—SHORTHAND TEST IN ENGLISH (FOR THOSE WHO QUALIFY AT THE WRITTEN TEST).

Marks—300.

Note (i).—Candidates will be given two dictation tests in English, one at 120 words per minute for seven minutes, and another at 100 words per minute for ten minutes, which they will be required to transcribe in 45 and 50 minutes respectively.

Note (ii).—Candidates who satisfy the minimum qualifying standard in the dictation at 120 words per minute will rank above the candidates who obtain the same standard in the dictation at 100 words per minute, persons in each group being arranged inter se in order of their merit as disclosed by the aggregate marks awarded to each candidate.

Note (iii).—Candidates will be required to transcribe their shorthand notes on typewriters and for this purpose they will be required to bring their own typewriters with them.

- 2. The syllabus for the examination will be as shown in the attached schedule.
 - 3. All question papers must be answered in English.
- 4. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write down answers for them.
- 5. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all subjects at the examination.
- 6. Only those candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written test as may be fixed by the Commission in their discretion will be called for shorthand tests.

- 7. From the marks assigned to candidates in each subject, such deduction will be made, as the Commission may consider necessary, in order to ensure that no credit is allowed for merely superficial knowledge.
- 8. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks for the written subjects will be made for illegible handwriting.
- 9. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination.

SCHEDULE

Standard and syllubus of the examination

NOIE.—The standard of the question papers in Part A will be approximately that of the Matriculation examination of an Indian University.

English.—The paper will be disigned to test the candidates' knowledge of English Grammar and Composition, and generally their power to understand and ability to write correct English. Account will be taken of arrangement, general expression and workmanlike use of the language. The paper may include questions on essay writing; precis writing; drafting; correct use of words, easy idioms and prepositions; direct and indirect speech, etc.

General Knowledge.—Some knowledge of the Constitution of India, Five Year Plans, Indian History and Culture, general and economic geography of India, current events, everyday science and such matters of every day observation as may be expected of an educated person. Candidates' answers are expected to show their intelligent understanding of the questions and not detailed knowledge of any text book.

APPENDIX II

Brief particulars relating to the Services/posts to which recruitment is being made through this examination.

A. The Central Secretariat Stenographers' Service

The Central Secretariat Stenographers' Service has at present two grades as follows:--

Grade I:—Rs. 350—25—650 (Persons promoted from Grade II are allowed a minimum salary of Rs. 400 in this scale).

Grade II:—Rs. 210—10—270—15—300—E.B.—15—450—E.B.—20—530.

- (2) Persons recruited to Grade II of the Service will be on probation for a period of two years. During this period, they may be required to undergo such training and to pass such examinations as may be prescribed by Government.
- (3) On the conclusion of the period of probation, Government may confirm the person concerned in his appointment or, if his work or conduct, in the opinion of Government, has been unsatisfactory, he may either be discharged from the Service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.
- (4) Persons recruited to Grade II of the Service will be posted to one of the Ministries or Offices participating in the Central Secretariat Stenographers' Service Scheme. They may, however, at any time be transferred to any other such Ministry or office.
- (5) Persons recruited to Grade II of the Service will be eligible for promotion to the next higher grade in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.
- (6) Persons appointed to Grade II of the Service in pursuance of their option for that service will not, after such appointment have any claim for transfer or appointment to any post included in the Cadre of the Indian Foreign Service (B) or the Railway Board Secretariat Service Scheme.
- B. Railway Board Secretariat Stenographers' Service
- (a) The service conditions of Stenographers employed in the Ministry of Railways so far as recruitment, training, promotion, etc. are concerned, are regulated by the Railway Board's secretariat Stenographer's Service Scheme, which is on the lines of the Central Secretariat Stenographers' Service Scheme.
- (b) The Railway Board Secretariat Stenographers' Service consists of the following two grades,
 - (i) Stenographers' Grade I-Rs, 350-25-650,
 - (ii) Stenographers' Grade II—Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530.

Direct recruitment is made in Grade II only. The posts in Grade I are filled by promotion from amongst Grade II Stenographers. Grade II Stenographers on promotion to Grade I are allowed a minimum pay of Rs. 400 per month.

Grade I Stenographers are also considered for promotion as Section Officers in accordance with the rules in force from time to time against the quota reserved for them.

(c) The Railway Board's Secretariat Stenographers' Service is confined to the Ministry of Railways and the staff are not liable to transfer to other Ministries as in the Central Secretariat Stenographers' Service.

- (d) Officers of the Railway Board's Stenographers Service recruited under these rules:
 - (i) will be eligible for pensionary benefits and
 - (ii) shall subscribe to the non-contributory State Railway Provident Fund under the rules of that fund as are applicable to Railway servants appointed on the date they join service.
- (e) The staff employed in the Ministry of Railways are entitled to the privilege of passes and privilege ticket orders on the same scale as are admissible to other Railway Staff.
- (f) As regards leave and other conditions of service, staff included in the Railway Board's Secretariat Stenographers' Service are treated in the same way as other Railway staff but in the matter of medical facilities they will be governed by rules applicable to other Central Government employees with headquarters at New Delhi.
- C. Indian Foreign Service (B)—Grade II of the Steno-graphers Sub-cadre.

The scale of Grade II of the SSC of the Indian Foreign Service (B) is Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530. The officers appointed to Grade II of the SSC of the I.F.S. (Branch 'B') will be governed by the I.F.S. Branch 'B' (RCSP) Rules 1964, I.F.S. (PLCA) Rules, 1961 as made applicable to I.F.S. 'B' officers and such other rules and orders as may be made applicable to them by the Government of India.

The Indian Foreign Service Branch 'B' is confined to the Ministry of External Affairs and Indian Missions abroad and the officers appointed to this service are not normally liable to transfer to other Ministries except the Ministry of Commerce. They are, however, liable to serve anywhere inside or outside India.

During service abroad, IFS(B) officers are granted foreign allowance in addition to their basic pay at rates which may be sanctioned from time to time, depending upon the cost of living etc. of the countries concerned. In addition, the following concessions are also admissible during service abroad, in accordance with the IFS (PLCA) Rules, 1961, as made applicable to IFS(B) Officers:—

- (i) Free furnished accommodation according to the scale prescribed by the Government,
- (ii) Medical Attendance Facilities under the assisted Medical Attendance Scheme.
- (iii) Annual return air passage for children between the ages of 8 and 18, studying in India to visit their parents during the long vacation subject to certain conditions.
- (iv) An allowance for the education of children up to a maximum of two children between the ages of 5 and 18 at rates prescribed by Government from time to time.
- (v) Outfit allowance in connection with service abroad, in accordance with the prescribed rules and at rates fixed by Government from time to time. In addition to ordinary outfit allowance, special outfit allowance is admissible to officers posted in countries, where abnoramlly cold climatic condition exist.
- (vi) Home leave passage for officers and their families in accordance with the prescribed rules.

The revised leave Rules, 1933 as amended from time to time, will apply to members of the service, subject to certain modifications. For service abroad, except in some neighbouring countries, officers are entitled to an additional credit of leave to the extent of 50 per cent of leave admissible under the Revised Leave Rules.

While in India, Officers are entitled to such concessions as are admissible to other Central Government Servants of equal and similar status.

Officers of the IFS(B) are governed by the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, as amended from time to time and by orders issued thercunder.

Officers appointed to this service are governed by the Liberalised Pension Rules, 1950, as amended from time to time and by orders issued thereunder.

D. Election Commission, India

The posts of Stenographers in the Election Commission carry a scale of pay of Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530 like the posts of Stenographers in the Central Secretariat Stenographer's Service. These posts arc, however, not included in the Central Secretariat Stenographers' Service Scheme and the persons appointed to these posts will have no claim to be appointed to posts included in the cadre of the Central Secretariat Service.

E. Department of Tourism

The posts of Senior Stenographers in the Department of Tourism are sanctioned in the revised scale of Rs. 210—10—290—15—320—EB—15—425 and belong to General Central Service Class II (Non-Gazetted)—Ministerial. Senior Stenographers with at least five years' service are eligible for promotion in the post of personal Assistant in the pay scale of Rs. 320—15—470—EB—15—530. Candidates appointed on

the results of this examination will ordinarily be required to serve in the Head-quarters establishment of the Department but may be required to serve any where in India.

F. Armed Forces Headquarters Stenographers' Cadre

The posts of Stenographer Grade II are non-gazetted (Class III) temporary posts in A.F.H.Q. Stenographers Cadre which is confined to Armed Forces Headquarter and Inter Service Organisations. The cadre has, at present, two grades

Stenographer Grade I—Rs. 375—20—575—25—600, Stenographer Grade II—Rs. 210—10—270—15—300— EB—15—450—EB—20—530,

- 2. Persons recruited direct as temporary Sten grade II will be on probation for a period of Unsatisfactory record of service during this period result in discharge of the probationer from service. Stenographers 2 years.
 period mo
- 3. Stenographers Grade II recruited to AFHQ will be generally posted to one of the three Services HQ/Inter Service Organisations located in Delhi/New Delhi. They will, however, also be liable to be posted to such other stations outside Delhi/New Delhi where offices of AFHQ/Inter Service Organisations may be located.
- 4. Stenographers Grade II will be eligible for promotion to the post of Stenographer Grade I in accordance with the rules in force from time to time.
- 5. Leave, Medical aid and other conditions of service are the same as applicable to the other Ministerial staff employed in AFHQ.
- G. Department of Parliamentary Affairs

The scale of pay for the posts of Stenographer in the Department is Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—

Candidates appointed to the Service by selection through e competitive examination shall be on probation for a period of two years.

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 21st October 1965

No. 12/18/65-E.Pty.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 133-V of the Defence of India Rules, 1962, the Central Government is pleased to order that all property in India moveable and immoveable, belonging to, or held by, or managed on behalf of M/s. Victory Jute Products Ltd., 51-Ezra Street, Calcutta shall vest in the Custodian of Enemy Property for India.

No. 12/19/65-E.Pty.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 133-V of the Defence of India Rules, 1962, the Central Government is pleased to order that all property in India moveable and immoveable, belonging to, or held by, or managed on behalf of Messrs The Free School Street Property Ltd., 51 Ezra Street, Calcutta shall vest in the Custodian of Enemy Property for

P. K. J. MENON, Jt. Secy.

MINISTRY OF STEEL AND MINES (Department of Iron and Steel)

New Delhi, the 19th September 1965 AMENDMENT OF PUBLIC NOTICE PUBLIC NOTICE

Subject: -Introduction of I.S.I. Certification Marks Scheme for Steel.

No. SC(C)-2(44)/63.—The following amendment is made in para 4(b) of the Public Notice No. SC(C)-2(44)/63-III dated 11-5-65 published in the Gazette of India Part 1, Section 1 dated 22-5-65.

Substitute para 4(b) by the following:

"4(b) untested steel lying in stock with the Producers including Regd. Re-rollers and Secondary Producers/ Stockists etc. as at the midnight of 31-3-65/1-4-65 may be sold up to 31-3-66 at the prevailing prices of corresponding commercial specification on the date of despatch/delivery and if there are more than one grade in the corresponding commercial specifications then at the price applicable to the lowest of these grades."

S. C. MUKHERJEE, Dy. Iron and Steel Controller for Iron and Steel Controller."

CORRIGENDUM

New Delhi, the 20th October 1965

No. SC(A)-24(7)/64.—In the Department of Iron and Steel Notification No. SC(A)-24(7)/64 dated 23-3-1964 regarding nomination of Members on the Standing Committee (Trade) for Steel Industry, in the existing entry at S. No. 11.

Shri V, M, Panchal, Federation of Associations of Small Industries of India.

23-B/2, Rohtak Road, New Delhi-5.

READ

Shri G. D. Dalmia, Federation of Associations of Small Industries of India.

23-B/2, Rohtak Road, New Delhi-5,

Shri G. P. Dalmia will replace Shri V. M. Panchal as alternate representative of the Federation to the Iron and Steel Advisory Council, also.

A. K. AGARWAL, Under Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY AND SUPPLY (Department of Industry)

RESOLUTION

New Delhi, the 13th October 1965

No. 9/2/65-Salt.—In supersession of the former Ministry of Commerce & Industry's Resolution No. 9/2/62-Salt, dated the 9th April 1963, the Government of India have decided to reconstitute the Central and the Regional Advisory Boards for Salt. The functions of the Central Board will be to advise the Government of India on the administration of the proceeds of the salt cess levied under section 3 of the Salt Cess Act, 1953, and to make recommendations generally for measures conducive to the development of the salt industry. industry, e.g.

- establishment and maintenance of research stations, model farms and salt factories;
- (ii) fixing the grades of salt and improving its quality;
- (iii) development of exports; (iv) promoting and encouraging among manufacturers of salt; effort co-operative
- (v) promoting the welfare of labour employed in the salt industry, and
- (vi) any other matter pertaining to the development of the salt industry in general,

The functions of the Regional Boards will be to make recommendations on similar lines to the Central Board in so far as their respective areas are concerned.

2. The composition of the reconstituted Central and Regional Boards will be as follows:

A. CENTRAL ADVISORY BOARD

Chairman

1. The Officer-on-Special Duty, Ministry of Industry and Supply, concerned with the administration of

- The Deputy Secretary, Ministry of Industry and Supply, concerned with the administration of 'Salt'.
- 3. A representative of the Ministry of Finance.
- The Deputy-Director Incharge, Central Salt & Marine Chemicals Research Institute, Bhavnagar.
- The Deputy Director General, Directorate General of Technical Development, Ministry of Industry and Supply, New Delhi.
- 6-7. Two representatives from the Governments of the major Salt producing States of Madras, Andhra Pradesh, Maharashtra, Gujarat and Rajasthan to be nominated by the Central Government by rotation. The representatives during the tenure of the present Board will be one each from the Governments of Rajasthan and Maharashtra.
- 8-9. Two representatives from the Governments of the 7 above to be nominated by the Central Government by rotation. The representatives during the tenure of the present Board will be one each from the Governments of Assam and U.P.
- 10-14. One person each to be nominated by the Central Government from the States of (1) Madras, (2) Andhra Pradesh, (3) West Bengal and Orissa, (4) Maharashtra and (5) Gujarat, who, in the opinion of the Central Government, has knowledge and experience of Salt manufacture in the area, namely: namely :-
 - (i) Shri M. M. Gurunath,3, Lakshman Chettiar St.,T. Nagar,Madras-17.
 - (ii) Shri A. Suryanarayana Rao, Appanna House, Visakhapatnam-1,

- (iii) Shri M. Yusuf, C/o Messrs. Orissa Salt Manufacturers Association, Cuttack.
- (iv) Siri Jayanthi Lal Tribubandas, Chairman, Bombay Salt Merchants' Association, Jambali Naka, Thana, Bombay.
- (v) Shri S. M. Antani, C/o Kuich Salt & Allied Ind., Kandla (Gujarat)
- 15. A person to be nominated by the Central Government, who in their opinion, has knowledge and experience of the salt trade, namely:—

Shri Srinivas Patehpuria, C/o Messrs. Jamnadas Srinivas (P) Ltd., 82/2, Muktaram Babu St., Calcutta-7.

- 16-17. Two persons to be nominated by the Central Government, who, in their opinion, have know-ledge and experience of public affairs, namely:—
 - (i) Shri G. L. Oza, M.P., Vatsalya Vidyanagar, Rajkot-2,
 - (ii) Shri M. Thirumala Rao, M.P., Gandhinagar, Kakinada (Andhra Pradesh).
 - 18. A person to be nominated by the Central Government, who in their opinion, has knowledge and experience of labour problems:—

Name will be announced later.

19. A person to be nominated by the Central Government, who, in their opinion, has knowledge and experience of the salt-based chemical industries, namely:—

Shri D. S. Seth, C/o Messrs. Tata Chemicals Ltd., Bombay House, Fort, Bombay-1.

20. A person to be nominated by the Central Government, who, in their opinion, has knowledge and experience of the functioning of the salt manufacturing co-operative societies, namely:—

Shri Trambaklal J. Shukla, Chairman, Shri Gujarat Rajya Mitha Udyog Sahkari Sangh Ltd., Darasar Road, Surrendranagar (Gujarat).

Member-Secretary

- 21. The Salt Commissioner.
- Note: Representatives of the Ministry of Railways, Ministry of Transport, State Trading Corporation, and the 'Export Promotion' Wing of the Ministry of Commerce may be invited to attend meetings of the Central Advisory Board, when necessary.

B. REGIONAL ADVISORY BOARDS

1. MADRAS,

Chairman

1. The Salt Commissioner,

Members

- 2. A representative of the Government of Madras.
- 3-4. Two persons to be nominated by the Central Government, who, in their opinion, have know-ledge and experience of labour problems:—
 - (i) Names will be announced later.
 - (ii) Names will be announced later.
- 5-6. Two persons to be nominated by the Central Government, who, in their opinion, have knowledge and experience of salt manufacture in the area, namely:—
 - (i) Shri C. I. R. Machado, Fatima Lodge, 9, Manal Street. Tuticorin-1.
 - (ii) Shri P. Lakshminarayan Naidu, 397, T. H. Road, Madras-21.
- 7-8. Two persons to be nominated by the Central Government, who, in their opinion, have knowledge and experience of public affairs, namely:—
 - (i) Dr. P. Srinivasan, M.P., 4B, Ratnasabhapati Mudaliar Road, Madras-21.
 - (ii) Shri V. Vairava Thevar, M.P. (Lok Sabha), Kundamarai Kadu Village, Kuruvikkarambai Post, District Thanjavur (Madras).

Member-Secretary

9. The Deputy Salt Commissioner, Madras.

2. ANDHRA PRADESH

Chairman

1. The Salt Commissioner.

Members

- 2. A representative of the Government of Andhra Pradesh,
- 3-4. Two persons to be nominated by the Central Government, who, in their opinion have knowledge and experience of labour problems:—
 - (i) Names will be announced later.
 - (ii) Names will be announced later.
- 5-6. Two persons to be nominated by the Central Government who, in their opinion, have knowledge and experience of salt manufacture in the area, namely:—
 - (i) Shri A. Suryanarayana Murthy, Appna House, Visakhapatnam-1, (Andhra Pradesh).
 - (ii) Shri P. Chandra Sekhara Reddy, Major Licensce, Iskapalli Factory, Allur Post, Nellore District.
- 7-8. Two persons to be nominated by the Central Government, who, in their opinion, have knowledge and experience of public affairs, namely:—
 - (i) Shri M. S. Murti, M.P., Kondakaria P.O., Via Anakapalle, Visakhapatnam District (Andhra Pradesh).
 - (ii) Shri B. Rajagopala Rao, M.P., P.O. Amadalavalasa, District Srikakulam, Andhra Pradesh.

Member-Secretary

9. The Deputy Salt Commissioner Madras.

3. WEST BENGAL & ORISSA

Chairman

1. The Salt Commissioner.

Members

- 2-3. A representative each of the Governments of West Bengal and Orissa.
- 4-5. Two persons to be nominated by the Central Government, who, in their opinion, have knowledge and experience of labour problems:—
 - (i) Names will be announced later.
 - (ii) Names will be announced later.
- 6-7. Two persons to be nominated by the Central Government, who, in their opinion, have ledge and experience of salt manufacture in the area, namely:—
 - (i) Shri Sarbotosh Bera, Director, Great Bengal Salt Company Ltd.
 - (ii) Shri T. Sivaramyya,
 Vice-President,
 The Human Salt Production Sales Cooperative Society Ltd.,
 P.O. & District Ganjam,
 Orissa.
- 8-10. Three persons to be nominated by the Central Government, who, in their opinion, have knowledge and experience of public affairs, namely:—
 - (i) Shri S. C. Samanta, M.P., P.O. & Village Tamluk; District Midnapur, West Bengal.
 - (ii) Shri Karunakar Panigrahi, M.L.A., Bhubaneswar.
 - (iii) Shrimati Ila Palchoudhri, 64, Lake Place, Calcutta-29.

Member-Secretary

11. The Assistant Salt Commissioner, Calcutta.

4. MAHARASHTRA

Chairman

1. The Salt Commissioner.

Members

- 2. A representative of the Government of Maharashtra.
- 3-4. Two persons to be nominated by the Central Government, who, in their opinion, have knowledge and experience of labour problems:—
 - (i) Shri S. G. Karnik,
 Mithagar Kamgar Union,
 115, Satyagiri, Dadar Main Road,
 Dadar, Bombay-14.

- (ii) Shri R. B. Patil, Mithagar Kamgar Union, 115, Satyagiri, Dadar Main Road, Dadar, Bombay-14.
- 5-6. Two persons to be nominated by the Central Government, who, in their opinion, have knowledge and experience of salt, manufacture in the area, namely:—
 - (i) Shri M. A. Bhaijee, Vice-President, Uran Salt Merchants & Shilotries Syndicate, Uran.
 - (ii) Nadirshah Perozshah Barthania, C/o Nadirshah Perozshah & Co., Above State Bank, Abdul Rehman Street, Bombay.
- 7-8. Two persons to be nominated by the Central Government, who, in their opinion, have know-ledge and experience of public affairs namely:—
 - Shri N. S. Kajrolkar, M.P., 185, Dr. Ambedkar Road, Parel, Bombay-12.
 - (ii) Shri Shankar Babaji Sawant, M.L.A., Kakartale, P.O. Mahad, District Kolaba, Maharashtra State
 - 9. The Director of Industries, Government of Goa, Daman and Diu, Panjim.

Member-Secretary

10. The Deputy Salt Commissioner, Bombay.

5. GUJARAT

Chairman

1. The Salt Commissioner.

Members

- 2. A representative of the Government of Gujarat.
- 3-4. Two persons to be nominated by the Central Government, who in their opinion, have know-ledge and experience of labour problems:—
 - (i) Names will be announced later.
 - (ii) Names will be announced later.
- 5-6. Two persons to be nominated by the Central Government, who, in their opinion, have knowledge and experience of salt manufacture in the area, namely:—
 - (i) Shri B. R. Kamdar, Chairman, Saurashtra & Kutch Salt Manufacturers' Association, Jamnagar.
 - (ii) Shri Kalyanbhai T. Shah,
 C/o Gujarat Vepari Mahamandal,
 P.O. No. 162,
 Ahmedabad.
- 7-8. Two persons to be nominated by the Central Government, who, in their opinion, have knowledge and experience of public affairs namely:—
 - Shri M. B. Vaishya, M.P., 17, Sutariya Society, Outside Shahpur Gate, Ahmedabad,
 - (ii) Shri T. M. Dave, M.L.A., Khandi Pol, Wadhwan City, District Surendranagar, Gujarat State.
 - 9. The Director of Industries, Government of Goa, Daman and Diu, Panjim.

Member-Secretary

The Deputy Salt Commissioner, Bombay.
 RAJASTHAN

Chairman

1. The Salt Commissioner

Members

- 2. A representative of the Government of Rajasthan.
- 3-4. Two persons to be nominated by the Central Government, who, in their opinion, have knowledge and experience of labour problems:—
 - (i) Names will be announced later.
 - (ii) Names will be announced later,

- 5-6. Two persons to be nominated by the Central Government, who, in their opinion, have knowledge and experience of salt manufacture in the area, namely:—
 - (i) The General Manager, Rajasthan Government Salt Sources, Jaipur.
 - (ii) Shri Gopi Krishan Totla, Rajasthan Salt Industries, Sambhar Lake (Rajasthan).
- 7-8. Two persons to be nominated by the Central Government, who, in their opinion, have know-ledge and experience of public affairs namely:—
 - Shri Jaswantrai Mehta, M.P., Ladhnu House, Jodhpur.
 - (ii) Shri Motilal Choudhri, M.L.A., Didwana.

Member-Secretary

- The Deputy Salt Commissioner, (Headquarters), Jaipur.
- 3. (a) The Central and the Regional Advisory Boards will have a term of 2 years from the date of their formation.
- (b) If a non-official seat on a Board falls vacant, the Central Government shall make fresh nomination to fill up the vacancy. The person so nominated shall hold office for the unexpired portion of the term of the Board.
- (c) If a nominated member in unable to attend a meeting, he will intimate the fact in writting addressed to the Chairman of the Central or the Regional Board as the case may be.
- (d) The quorum for a meeting shall be 7 for the Central Board and 3 for the Regional Boards except for the West Bengal and Orissa Regional Board for which the quorum shall be 4.
- (e) Every non-official member attending a meeting of the Central or Regional Board or of a sub-committee duly constituted on the recommendation of the Board shall be entitled to travelling allowance and daily allowance as admissibe under the rules or approved by the Central Government from time to time. All M.P. Members of the Regional Boards may attend the meetings of the Central Board and members of the Central Board having knowledge and experience of salt manufacture from a particular area may attend the meetings of the Regional Board for that area.
- (f) A non-official member may resign his office by letter addressed to the Chairman of the Central or Regional Board, as the case may be.
- (g) If a non-official member leaves India, he shall intimate to the Chairman of the Board concerned, before leaving India, the date of his departure from and the date of his expected return to India, and if he intends to be absent from India for a period longer than 6 months, he shall tender his resignation. If any such member leaves India without complying with the above, he shall be deemed to have resigned with effect from the date of his departure from India.
- (h) A member shall be declared by the Chairman concerned to have vacated his office.
 - (i) if he becomes insolvent, or
 - (ii) if he is convicted of any offence, which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude, or
 - (iii) if he is absent from 3 consecutive meetings of the Board without leave of absence from its Chairman, or
 - (iv) if, in the opinion of the Central Government it is undesirable that he should continue to be a member of the Board.
- (i) The Secretary of the Boards, with the approval of the Chairman of the Central Board, may invite one or more non-official members of other Boards or other persons to attend any meeting of a Board, and such members or persons shall be entitled to travelling allowances etc. as indicated under clause (e).
- (j) The Board shall meet at such place and time as may be appointed by its Chairman.
- (k) A notice shall be given to every member present in India of the time and place fixed for each ordinary meeting at least 15 days before such meeting and each member shall be furnished with a list of business to be disposed of at that meeting.

Provided that when an emergent meeting is called by the Chairman, such notice shall not be necessary.

(1) No business, which is not on the list, shall be considered by a meeting without the permission of the Chairman of the Board concerned.

- (m) The Chairman shall preside over the meetings of the Board at which he is present. If the Chairman is absent from any meeting, the members present shall elect one of the members to preside over the meeting and the member so elected shall at that meeting exercise all the powers of the Chairman.
- (n) Every question at a meeting of the Board shall be decided by a majority of votes of the members present and voting on that question. In the case of equal division of votes, the Chairman shall give an additional vote,
- (o) The proceedings of each meeting of the Board shall be circulated to all members present in India and thereafter recorded in a Minute Book, which shall be kept for permanent

The record of the proceedings of each meeting shall be signed by the Chairman of the Board.

(p) Proposals for expenditure in a Region to be met from the proceeds of the Salt Cess shall be considered first by the Regional Board. For this purpose, preliminary estimates detailing the proposal and its estimated cost together with other necessary data shall be prepared by the Regional Officers. The proposals together with the Regional Board's recommendation shall then be considered by the Central Phoand Board.

Works of developmental nature and labour welfare, costing up to Rs. 40,000 each may be approved for execution by the Regional Boards themselves without referring them to the Central Advisory Board for their final recommendations.

- The recommendations of the Central Board shall be submitted to the Central Government for acceptance after which detailed estimates shall be prepared. The estimates shall be sanctioned by competent authority.
- (r) No act or proceeding of the Central Board or any of the Regional Boards shall be called in question on the ground merely of the existence of any vacancy in, or defect in the constitution of, the Central Board or, as the case may be, any of the Regional Boards.

ORDER

Ordered that this Resolution be communicated to all State Governments, all Ministries of the Government of

India, Planning Commission, Cabinet Secretariat and Prime Minister's Secretariat.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India, Part I, Section 1.

D. N. KRISHNAMURTHY, Under Secy.

(Department of Supply and Technical Development)

RESOLUTION

New Delhi, the 13th October 1965

No. 19(1)/65-PI.—The Government of India in the Ministry of Industry & Supply (Department of Supply & Technical Development) appointed on July 27. 1964, a Study Team under the Chairmanship of Shri A. N. Vidyalankar, Member of Parliament, to examine the Organisation, structure, methods of work and procedures of the Directorate General of Supplies & Disposals, particularly with a view to locating the points at which delays occur, where bottlenecks exist and where administrative failures are possible and to suggest measures for improvements so that opportunities for corruption are eliminated. corruption are eliminated.

- 2. The Study Team submitted its Interim Report to Ministry of Industry & Supply (Department of Supply Technical Development) in December, 1964.
- decisions of the Government thereon are set out in Annexure. the in the
- Government wish to place on record their appreciation of the valuable work done by the Study Team,

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

N. R. BANSOD, Jt. Secv.

ANNEXURE

Recommendations of the Study Team Sl. No.

Chapter III-Organisation-The Purchase Section

- . The experiment of creating a Planning and Tender Enquiry Cell and Contract Cell under the charge of an Assistant Director of Supplies and Section Officer respectively in a Purchase Directorate whereby the functions of issuing tender enquiries and contracts have been centralized should be continued and extended further.
- 2. On an experimental basis the following measures should additionally be taken in two Directorates:—
 - (a) A Purchase section should be under the charge of either of an Assistant Director or Section Officer.
 - (b) A Section should have 2 to 3 Assistants/U.D.Cs. and 2 L.D.Cs. One stenotypist should be given to the Officer-in-charge of the Section.
 - (c) Separate Sections should be organised for Rate and Running Contract items and placed charge of Section Officer, under the
 - (d) Assistant Directors should be put in char section dealing with procurement of stores are not on Rate and Running Contracts. charge which

Chapter IV-Organisation-Organisation & Methods

3. O.&M. Unit should be strengthened and should also have a work study team. It should be placed under a whole-time Director who should have 2 Section Officers with 2 Assistants each in addition to the present staff. This Directorate will lay down norms of work, define job content, carry out work studies and case studies with a view to improving procedures, assessing staff requirements and apprising the quantity and quality of work done.

lanning & Development Division

- 4. The Planning Directorate should be revived and called the Planning and Development Division. It should attend to the following items of work:—
 - (a) Drawing up of a comprehensive programme for receipt and bulking of indents for common user items from all the major indentors.
 - (b) Rationalisation of sizes and specifications and making of advance arrangements for raw materials for planned production up to the optimum capacity.
 - (c) Examining of the load and capacity of each production unit and recommending placing orders on the basis to ensure timely delivery of stores.

Decision of the Government

Accepted.

Accepted.

Accepted.

Accepted.

Accepted.

It has generally been agreed that for proper supervision and direction of case studies to be undertaken by the DGS&D, the O&M Unit should be suitably strengthened, and the question of posting a Director should be examined when final proposals on the staffing pattern of the Vigilance, O&M, and Complaints Sections are received.

The Government had already decided that the Planning Dte. of the DGS&D should be revived. The Study Team would recommend in their final report the precise staffing pattern.

SI. No. Recommendations of the Study Team

Decision of the Government

- (d) Preparing a standard vocabulary of stores.
- (e) Encouraging and maximising indigenous production through standardisation and the conclusive of long term contracts for stores in short supply.
- (f) Determining and deciding the extent to which prescribed specifications can be relaxed having regard to limitations of local manufacture.
- 5. This Division should have a suitable complement of technically qualified staff for systematic studies of imported stores requiring the use of imported raw materials with a view to reduce the burden of Foreign Exchange resources.
- 6. For the consideration of cases, a standing Development Committee consisting of a representative of Planning & Development Division, Department of Technical Development, Council of Scientific and Industrial Research and Inspection Wing of DGS&D should be formed. The representative of this Division should act as the convenor.
- 7. This Division should also help in assessing the reasonable manufacturing cost of certain items on the basis of which negotiations could be undertaken with likely suppliers.

Chapter V-Trulning of Officers and Staff

- 8. For all Assistants, U.D.Cs., J.F.Os. J.P.Os. and Technical Assistants appointed during the last three years training course should be organised each for a period of 2 months for about 1½ hours each day. (The training should be given on (i) the Organisation and Functions of the D.G.S.&D. (ii) The General Principles of Contracts (iii) Purchase Procedures (iv) Progressing of Supplies (v) Settlement of claims of Finalisation (vi) Audit objection and (vii) Discussion on Typical cases).
- 9. For all Assistant Directors of Supply who are already employed, seminars and Symposia should be arranged for a period of one month. (During these discussions typical case-studies techniques of supervision, management, work planning and control and public relations should be discussed. Discussions on problems faced by different officers can also take place).
- 10. The Training Section should be under the charge of a good Section Officer assisted by one Assistant. The training programme should be administered by the Director O.&M. who should have the syllabus and the instruction papers prepared.

Chapter VI-Purchase-Registration of Firms

- 11. The registration of the firm should not be held up for non-submission of the Income Tax Clearance Certificate provided, of course bank report is good. Provisional registration should be made on an affidavit that at the time outbmission of the application the firm had cleared their previous year's assessment of Income Tax. However, the firm should be required to submit the Income Tax Clearance Certificate positively within one year of the provisional registration failing which the registration should be cancelled.
- 12. A small Scale Unit should not route its application for Registration through the Director of Industries of the State but should submit it direct alongwith a certified copy of the letter from the Director of Industries of the State Registering it as a small scale unit.
- 13. Large Scale Units should also be told reasons for non-registration as is being done in the case of Small Scale Units, except, of course, where registration has been refused on confidential grounds.
- 14. A fresh Inspection Report should not be necessary for registration for additional allied items or new items provided of course, a firm is considered capable of manufacturing certain stores on the basis of the previous Inspection Report. The Deputy Director (and not the Section Officer) should decide whether the firm would be capable of manufacturing the items for which registration is sought with the equipment available with it at the time of first registration or whether a fresh Inspection report is necessary.
- 15. The existing instructions enabling a Small Scale Unit which in the absence of testing facilities of its own can get its stores tested in a nearby Laboratory, to be registered need to be reiterated.
- 16. The staff for registration and for inspection of stores should be separated as far as possible.
- 17. For maintaining a check by the supervisory officer, all applications for Registration should be diarised separately and the diary closed every week to know the position of outstandings.

The Government had already decided that the Planning Directorate of the DGS&D should be revived. The Study Team would recommend in their final report the precise staffing pattern.

The Government had already decided that the Planning Directorate of the DGS&D should be revived. The Study Team would recommend in their final report the precise staffing pattern.

The Government had already decided that the Planning Directorate of the DGS&D should be revived. The Study Team would recommend in their final report the precise staffing pattern.

Accepted. It was agreed that a full time Section Officer would be necessary to impart the training and an additional post of S.O. be created. It was also agreed that on implementation of all the recommendations of the Study Team the net surplus staff, if any, after taking into account the reduction and additions to the requirements would be surrendered.

Accepted in principle. It was also accepted that a different course of training, preferably a condensed refresher course, should be organised for the existing Deputy Directors as well.

Accepted. The training programme would be administered by the Head of the O.&M. Division in the DGS&D.

Accepted.

Accepted.

Accepted,

Accepted. The Inspection Wing would be consulted before taking a decision whether or not a fresh capacity report is necessary.

Accepted. Necessary instructions to this effect have already been issued.

Accepted. The DGS&D will try to implement this decision in one or two circles on an 'experimental basis.'

Accepted.

Sl. No. Recommendations of the Study Team

Decision of the Government

- 18. The circulation of a weekly statement of firms which registered during the previous week should be discontinued as the trade-lists are not being properly maintained and tenders are not issued to many firms who are registered for months. The Registration Section should send a memo instead indicating the items for which the firm has been registered to the sections concerned so that immediate action can be taken to amend the trade-lists failing which responsibility should be fixed.
- 19. The DGS&D should amend those clauses of standard terms and conditions which are not in accordance with normal trade practice, are generally unacceptable to suppliers and are in fact amended in individual cases generally.
- 20. These terms and conditions should be scrutinised by a Committee consisting of the representatives of the DGS&D, Finance and Law, who should consult the representatives of trade.
- 21. Except when a case falls under above a firm habitually asking for a change in the DGS&D standard terms and conditions should be struck off the Government registration.
- 22. For the proper maintenance of performance cards the section should be strengthened by four additional clerks.
- 23. The performance cards should also show quantities accepted under deviation under price reduction. The firm in whose case the stores accepted by and large are under deviation should not be given contracts by DGS&D as they are instrumental in eliminating genuine suppliers by cutting prices.
- 24. There should be an annual review of performance cards by the Deputy Director of Registration during the period January to March reviewing previous year's performance.

Chapter VII-Purchase

A-Cotton Textiles

- 25. The Director of Supplies (Tex.), Bombay should be given the following enhanced powers:—
 - (a) Full powers to advertise demands against indents exceeding four lakhs.
 - (b) Full discretion to issue routine amendments to contracts not falling within his purchase powers e.g.
 - (i) Change of consignee's address.
 - (ii) Change of the Inspecting Officer.
 - (iii) Change in despatch instructions.
 - (iv) Acceptance of stores under deviation with price reduction in respect of quantities accepted.
 - (v) Granting extension of delivery period where indentor has concurred and there is no downward trend in prices (to be issued in consultation with his associated figance).
 - (vi) Full powers to provide for the Rate of Excise Duty where at the time of placement of the contract provision for payment of Excise Duty at the prevailing rates is made and where supplies have been made in time.
- 26. The delegations at (i) to (v) in 25 should be made to the other Regional Offices as well as to the Directorate at Headquarters.
- 27. Rate/Running Contracts should be concluded for items of repetitive nature such as Sewing Cotton, Buttons, Dusters and Towels. The scope of Rate Contracts with Khadi and Village Industries Commission should be extended to cover the entire country instead of Delhi and New Delhi.
- 28. The Defence specifications for various Textile items should be reviewed by the proposed Planning Development Division and relaxed under certain conditions.

The matter would be considered further.

Accepted.

It has been decided that no separate Sub-Committee should be constituted. The Study Team should examine in detail the terms and conditions of contracts as are applicable to specific commodities or stores and associate in their examination officers from the Ministry of Law, Department of Supply and Ministry of Finance as and when required.

Accepted.

It has been decided that the Study Team should review this recommendation in the light of the report of the Staff Inspection Unit in which they had recommended that performance cards alongwith other items could be maintained by utilising power sam machines installed by the DGS&D.

Accepted,

Accepted.

DS (Textiles), Bombay should be empowered to plan procurement of indents not exceeding Rs. 20 lakhs in value, and concurrence of local Finance should be obtained in respect of indents above Rs. 4 lakhs.

Accepted.

Accepted.

It has been decided that the Director of Supplies (Tex.) should be delegated powers of DDG and where financial implications were involved, he could amend the contract in consultation with local Finance where such consultation was normally required.

Enhanced powers had already been given to Director of Supplies (Tex.) for finalising cases involving acceptance of cotton textile under deviation with suitable price reduction on the basis of recommendations of the inspectorate concerned

Accepted.

Accepted in respect of excise duty relating to finished products against contracts not exceeding Rs. 30 lakhs in value

Accepted insofar as Directors at H. Qrs. and Regional Offices at Bombay and Calcutta are concerned. The Regional Offices at Kanpur and Madras have no accredited Finance; hence the enhanced powers should not be delegated to them.

Accepted,

Accepted in principle.

628 THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 6, 1965 (KARTIKA 15, 1887) [PART I— SEC. 1 Sl. No. Recommendations of the Study Team Decision of the Government B-Machine Tools & other Engineering and Technical Stores 29. Duplicate tenders should not ordinarily be referred to the indentor for scrutiny and for recommending the offer Accepted. acceptable to him. 30. Where on account of certain reasons a reference is inescapable it should be made only with the approval of Accepted. D.D.G. 31. This aspect should be borne in mind by O.&M. Unit when doing case studies and by superior officers when writing confidential reports. Accepted. C—Post-Tender Negotiations—Counter-offers & Scrapping of Tenders 32. DGS&D should avoid post-tender negotiations and counter-offers. If in exceptional cases negotiations and counter-offers have to be resorted to that should be done on a rational basis after the cost structure of the item has been properly worked out. Accepted in principle. 33. The practice of asking the last supplier (if he has not quoted against a tender) the reasons for not quoting and inviting him to quote should be banned altogether. Accepted except that there would be no ban to ask the last supplier the reasons for not quoting. 34. Scrapping of tenders should be done with the prior approval of the Deputy Director General. Suitable instructions relating to scrapping of tenders have already been issued by the Department of Supply. Chapter VIII-Inspection A-Reconsideration of Policy 35. Firms having adequate quality control and highly qualified technical officers, should be allowed to supply stores without inspection subject to a suitable guarantee to be furnished by them subject to the following safeguards:— Necessary instructions relating to waiver of physical inspection and acceptance of stores on manufacturer's warranty have already been issued by the Department of Supply in October 1964. (a) No relaxation be allowed in case safety items. (b) Where allowed, quality certification from the firm should be compulsory. (c) An adequate warranty from the firm should be insisted upon, (d) A judicious selection of firms should be done by a committee consisting of the DDG (Inspection). the DDG (Supply) and a representative of the Ministry of Supply not below the rank of Deputy Secretary. (c) The entire matter should, in the first instance, be given an experimental trial for one year after which the position should be reviewed. B-Jute Accepted in principle.

36. Based on the past performance of the suppliers of Jute Goods the condition of inspection before supply should be waived. The selection of such firms should be left to a committee consisting of the Director General of Supplies and Disposals, Deputy Director General of Supplies and Disposals and a representative of Department of Supply. The firm, so selected should also be asked to come under the appropriate I.S.I. Certification scheme. The firms should give a suitable guarantee regarding their goods which may be drafted by Government.

Chapter IX—Inspection (Miscellaneous)

- 37. Steps should be taken to lay down uniform inspection procedures and norms for the more important stores. The above work should be entrusted to a suitably qualified officer, say a Director of Inspection. If norms are laid down, additional staff can be given as and when there is increase in work load so that inspection work does not
- 38. Immediate arrangements should be made to diarise all the requests that are received at a central place and show how they have been distributed. Disposal of a request should also be entered in the Diary. This Diary should be checked every week by the Director of Inspection who would know the state of work load with each Inspector.
- 39. The diaries of Inspectors should also indicate the results of inspection *i.e.* quality of stores inspected and the quantity that was passed and rejected and these diaries should be checked by the Group-in-Charge every week instead of every month as done presently. Besides, advance weekly programme of Inspection should be drawn up for each Inspector keeping in view the work load pending with each Inspector and approved by the Officer-in-charge of the group. group.
- 40. A statement indicating the pending work with Inspector should be prepared in the prescribed form.

Accepted in principle.

Accepted.

Accepted.

Accepted.

Sl. No. Recommendations of the Study Team

- 41. The Inspection staff should spend more time in inspection rather in office. Small sub-centres of Inspection where firms are located at long distance from the Inspection office should also be opened, to obviate the necessity of all Inspecting Officers going to the Central Office every day in afternoon. Only Group Officer should go to the Central Office every day and get orders on various cases. Ordinary clarification should be obtained in the sub-centre.
- 42. The Inspecting Officers should be made sufficiently mobile and to do that the following should be done:—
 - (a) an imprest should be maintained in each Inspection Office so that T.A. advances can be given out of the imprest to the Inspecting Officers proceeding on tour.
 - (b) Priority should be given to the Inspecting Officers for getting various types of vehicles from Government quota.
 - (c) The Inspecting Officers should be permitted to travel by Air wherever they cannot get rail bookings expeditiously and there is a likelihood of delay on this account. Government should authorise the Director of Inspection to give this permission.

Decision of the Government

The suggestion that Inspection staff should spend more time in inspection rather in office has been accepted in principle.

Accepted. Imprests should be maintained in the Inspection Directorates at Bombay, Calcutta, Madras and New Delhi, to start with. It should be extended to other Regional Offices later, on review of the working of this system in the Directorates of Inspection.

Matter is under consideration.

Not Accepted.

MINISTRY OF HEALTH

RESOLUTION

New Delhi, the 22nd October 1965

No. F. 4-38/64-FP.II.—In partial modification of this Ministry's Resolution No. 4-38/64-FP.II dated the 15th July 1965, regarding Committee to study the question of legalisation of abortion in the country, the Government of India have decided that the Committee will now submit their report by the 31st December 1965, instead of the 31st October 1965.

BASHESHAR NATH, Under Secy.

MINISTRY OF EDUCATION

New Delhi, the 27th September 1965

No. 22(22)/62-SR.II.—The Government of India have decided to set up a National Committee for Biological Sciences consisting of the following:—

1. Prof. P. Maheswari, Chairman
Head of the Deptt. of Botany,
University of Delhi.
Delhi.

2. Dr. K. C. Bora, Biology Division. Atomic Energy Establishment, Trombay, Richardson and Cruddas Building, Byculla, Bombay.

3. Dr. A. R. Gopala-Ayengar,
Director, Biology Group,
Atomic Energy Establishment, Trombay,
Richardson and Cruddas Building,
Byculla. Bombay.

Byculla, Bombay.

4. Dr. B. P. Pal,
Director-General,
Indian Council of Agricultural Research,
New Delhi.

 Dr. N. K. Panikkar, Director, Indian Ocean Expedition, Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi.

 Dr. A. S. Paintal, Director, Vallabhbbai Patel Chest Institute, Delhi

 Dr. B. R. Seshachar, Head of the Deptt. of Zoology, University of Delhi. Delhi.

Rev. H. Santapau.
 Director.
 Botanical Survey of India.
 Calcutta.

 Dr. O. Siddiqi, Tata Institute of Fundamental Research, Colaba, Bombay

The functions of the National Committee will be to promote and co-ordinate in this country, the study of the various branches of Biological Sciences, more specially in relation to their international requirements, keeping in view the objects of the International Union of Biological Sciences, namely:—

(a) to promote the study of Biological Sciences;

 (b) to initiate, facilitate and co-ordinate research and other scientific activities which demand international co-operation;

- (c) to ensure the discussion and dissemination of the results of co-operative research;
- (d) to promote the organisation of international conferences and to assist the publication of their reports.

M. M. MALHOTRA, Dy. Secy.

New Delhi, the 22nd October 1965

No. F. 1-2/65-PE2.—In continuation of this Ministry's Notification No. F.1-2/65-PE2 dated the 14th July 1965, the All India Council of Sports has coopted:

 Lt. General M. S. Wadalia, Quiab Stud and Agricultural Farm, Gadiapur, P.O. Mahrauli, New Delhi-30

and

 Shri P. L. Mehta, 18, Kautilya Marg, Diplomatic Enclave, New Delhi-11

as members of the Council with immediate effect and up to the 15th July, 1967.

The 30th October 1965

No. F. 1-2/65-PE2.—In continuation of this Ministry's Notification No. F. 1-2/65-PE2, dated 22nd October, 1965, Her Highness Rajmata Maharani Vijaya Raje Scindia of Gwalior is nominated as a member on the All India Council of Sports with immediate effect and up to the 15th July, 1967.

R. L. ANAND, Under Secv.

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 22nd October 1965

No. E.&P.4/1/30/64.—Whereas there has been certain further change in the composition of persons representing the Government of India, on the Central Board for Workers' Education notified in the Ministry of Labour & Employment Notification No. E.&P. 4(24)/58, dated the 12th December 1958, published in the Gazette of India, Part I, Section 1 dated the December 20, 1958/Agrahayana 29, 1880, it is hereby notified for the information of the Public that in pursuance of rule (3)b of the Rules and Regulations of the sald Society, the Government of India hereby appoints Shrl F. H. Vallibhoy, Joint Secretary (Adm.) in the Department of Expenditure, Ministry of Finance as a member of the Central Board for Workers' Education vice Shri P. Sadagopan, Internal Financial Advisor & Ex-Officio Deputy Secretary with effect from the date of this notification.

2 Accordingly in the sald notification in the category of

- 2. Accordingly in the said notification in the category of person representing the Government of India, for the entry:
 - "3, Shri P. Sadagopan,
 Internal Financial Adviser and Ex-Officio Deputy
 Secretary—Representing Government of India."

The following entry shall be substituted:---

"3. Shri F. H. Vallibhoy,
Joint Secretary (Adm.),
Department of Expenditure,
Ministry of Finance,
New Delhi—Representing Government of India."

O. P. TALWAR, Under Secy.

RESOLUTIONS

New Delhi, the 27th October 1965

No. WB-2(19)/65/1.—In modification of the Ministry of Labour and Employment Resolution No. WB-2(1)/62(1), dated the 3rd May 1963, Shri N. K. Das is appointed as an independent member on the Central Wage Board for the Iron Ore Mining Industry, Calcutta, vice Dr. R. M. Honavar, resigned.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

No. WB-2(19)/65/2.—In modification of the Ministry of Labour and Employment Resolution No. WB-2(1)/62/2, dated the 3rd May 1963, Shri N. K. Das is appointed as an independent member on the Central Wase Board for Limestone and Dolomite Mining Industries, Calcutta, vice Dr. R. M. Honavar resigned.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

HANS RAJ CHHABRA, Under Secy.